

“नार्थ इण्डिया” के किस हिन्दी भाषी राज्य में कौनसी तीसरी भाषा पढ़ाई जाती है”

स्टालिन ने एक्स पर कटाक्ष किया, क्या तीन भाषा वाला फार्मूला उत्तर भारत के किसी राज्य में लागू होता है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 मार्च। इस समय दक्षिणी राज्यों में कथित रूप से “भाषाओं को थोपने” को लेकर चल रही बहस के अन्तर्गत, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज पलटवार करते हुये एक चुभती हुई बात कह दी। उन्होंने प्रश्न किया कि उत्तर भारत के किस हिन्दीभाषी राज्य में तीसरी भाषा पढ़ाई जाती है?
तीन-भाषा फार्मूले की अपनी आलोचना को और भी तीखी बनाते हुए, स्टालिन ने केन्द्र से पूछा कि क्या तीन-भाषा फार्मूला उत्तरी राज्यों में लागू है।
स्टालिन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी तथा आलोचकों के दोहरे मानदण्डों की पोल खोलते हुये कहा कि वे पहले यह क्यों नहीं बताते कि उत्तर भारत में कौनसी तीसरी भाषा पढ़ाई जा रही है।
स्टालिन ने “एक्स” पर कहा, “इकतारफा नीतियों के कुछ हिमायती, बड़े चिन्तित स्वर में पूछते हैं, “आप

- इसी लय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, अगर दो भाषाएँ ही ठीक ढंग से पढ़ाई जायें, विद्यार्थियों को तीसरी भाषा सीखने की जरूरत ही नहीं है।
- स्टालिन के बेटे उदयनिधी स्टालिन ने यह भी कहा, कि, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (नई शिक्षा नीति) के जरिये, छद्म रूप से केन्द्रीय सरकार हम पर हिन्दी थोपना चाहती है, जिसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
- दूसरी तरफ केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मनंद प्रधान ने कहा, कि, नई शिक्षा नीति के तहत, भारत सरकार का आशय है, कि देश की सभी भाषाएँ पढ़ायें। हमने नई शिक्षा नीति में कहीं भी नहीं कहा, कि तीसरी भाषा के तहत केवल हिन्दी ही पढ़ाई जायेगी।

तमिलनाडु के विद्यार्थियों को तीसरी भाषा को सीखने का अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं?” तो, ये लोग पहले यह क्यों नहीं बताते कि उत्तर में कौनसी तीसरी भाषा पढ़ाई जा रही है? अगर उन्होंने केवल दो भाषाएँ वहाँ अच्छी तरह पढ़ाई हैं तो हमें तीसरी (भाषा) को पढ़ने की जरूरत कहाँ है?”
मुख्यमंत्री की ये टिप्पणियाँ

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री तथा उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन के सख्त बयान के बाद आयी हैं, जिन्होंने राज्य में हिन्दी थोपने के केन्द्र के कथित प्रयासों का विरोध किया था।
रविवार को उदयनिधि ने कहा था कि तमिलनाडु, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एन.ई.पी.) या किसी भी रूप में हिन्दी थोपने की कभी स्वीकार नहीं

करेगा।
उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया था कि एन.ई.पी. के जरिए “अप्रत्यक्ष रूप से” हिन्दी को थोपने की कोशिश की जा रही है, जबकि राज्य लम्बे समय से ऐसी नीतियों का प्रतिरोध करता आ रहा है।
तमिलनाडु सरकार ने 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एन.ई.पी.) लागू करने का सख्ती से विरोध किया है और इस नीति के “तीन-भाषा फार्मूले” को लेकर चिंता जताई है तथा आरोप लगाया है कि केन्द्र हिन्दी “थोपना” चाहता है।
बहस के दूसरे पक्ष में, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मनंद प्रधान ने एन.ई.पी. की तीन-भाषा-नीति के पीछे के सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट किया था कहा कि नई शिक्षा नीति सभी भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिये तैयार की गई है।
प्रधान ने हरिद्वार में कहा, “नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एन.ई.पी.) 2020 को सभी भाषाओं को महत्व (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेपर लीक मामले में फरार सुरेश ढाका के भाई की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, 3 मार्च। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में फरार चल रहे सुरेश ढाका के भाई कमलेश की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी सुनील रणवाह ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पेपर लीक से जुड़े दो अन्य मामलों में भी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। ऐसे में यदि उसे जमानत दी गई तो वह पुनः समान प्रकृति के अपराधों में लिप्त हो सकता है। इसलिए आरोपी को जमानत अर्जी को खारिज किया

■ सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने कहा कि आरोपी पेपर लीक से जुड़े दो अन्य मामलों में भी न्यायिक अभिरक्षा में है इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण के दस्तावेजों को लेकर विरोधाभास है। प्रार्थी के खिलाफ कोई सीधा साक्ष्य भी नहीं है। उस पर सोवनी कुमारी को प्रश्न पत्र मूहैया करने का आरोप है और सोवनी को पूर्व में ही जमानत दी जा चुकी है। मामले में उसे केवल सोवनी के साथ मोबाइल वार्ता के आधार पर ही शान्तिविक्रम दिया गया है। जिस स्थान पर बस में अभ्यर्थियों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका ने सोच-समझ कर जाल फेंका था, जैलैंस्की को फंसाने के लिए

पर ट्रम्प-जैलैंस्की प्रकरण से सबसे ज्यादा हानि हुई, तो ट्रम्प को

-अंजन राय-
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 मार्च। गत शुरुवात को वाइट हाउस में जो हंगामा हुआ, उसने यदि किसी को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है, तो वो है डॉनल्ड ट्रंप। इस घटना ने ट्रंप के उस वादे को खारिज कर दिया कि वो एक दिन में हाथ की करामत से यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे। अब यूक्रेन में युद्ध कहीं अधिक जटिल लग रहा है।
पश्चिमी मीडिया अब जैलैंस्की-ट्रंप झड़प के हर संभव परिणाम को बड़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा है। इस बात की व्यापक निंदा हो रही है कि आक्रामकता का सामना कर रहे एक देश के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। मीडिया में भारी चर्चा है कि अमरीकियों ने यूक्रेन के नेता के लिए जानबूझकर जाल बिछाया था।
मीडिया में यह भी चर्चा है कि इस खेल में अमेरिका, रूस द्वारा रचितनियमों के अनुसार खेल रहा था, रूसी लोग जैलैंस्की को सत्ता में नहीं देना चाहते। इसलिए उन लोगों ने यह नारा दिया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अपनी अवधि समाप्त कर चुके हैं इसलिए अब वो लोगों

- अमेरिका, रूस द्वारा लिखित कथानक के अनुसार खेल रहा था। रूस ने प्रचारित किया था, कि जैलैंस्की का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अतः उन्हें हटाकर यूक्रेन का नया राष्ट्रपति बनाना चाहिये, पर, ट्रम्प-जैलैंस्की झड़प के बाद, अमेरिका का यह “प्लान” उजागर हो गया और फेल हो गया।
- साथ ही, “रेयर अर्थ” खनिजों को यूक्रेन की भूमि के नीचे से निकालकर, उसका व्यवसायीकरण करने का अमेरिका का इरादा असफल हो गया है।
- ट्रम्प, नोबल का शान्ति पुरस्कार पाने का सपना देखने लगे थे, पर, अब यह स्वप्न ही रह गया है।
- यूक्रेन-रूस युद्ध को खत्म कराने के जो समाधान ट्रम्प प्रस्तावित कर रहे थे, उनमें न ही यूक्रेन का और न ही यूरोप के अन्य देशों का रोल था, पर, अब उल्टा ही हो रहा है। ट्रम्प-जैलैंस्की की झड़प के बाद यूरोप व यूक्रेन मिलकर समाधान ढूँढ रहे हैं, तथा, उनका इरादा अमेरिका को इस बारे में बाद में बताने का है।

के संवैधानिक प्रतिनिधि नहीं रहे।
ट्रंप, रूस के रुख को, खासकर व्लादिमीर पुतिन के रुख को दोहरा रहे थे। ऐसा लगता है कि अमेरिकियों ने वही मांगा है जो पुतिन ने कहा था- जैलैंस्की के स्थान पर किसी अधिक लचीले व्यक्ति को सत्ता में लाया जाए। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से नाराज विपक्ष ने वॉक आउट किया

मुख्य सचेतक ने कहा कि सदस्यों को सावचेत करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है कि बिना तथ्यों के बात सदन में नहीं रखें

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर, 3 मार्च। राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया और सदन का बहिर्गमन (वॉक आउट) किया।
सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने शून्यकाल में सुभाष गर्ग के खिलाफ यह प्रस्ताव पेश किया, जिसका कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने आग्रह किया कि इसकी जांच कराकर इसे निरस्त किया जाये और इसे पास नहीं किया जाये। इसके बाद सदन ने इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। इससे पहले जोगेश्वर

■ जोगेश्वर गर्ग का कहना था, कि “विधायक सुभाष गर्ग ने गत 24 फरवरी को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भरतपुर के लोहागढ़ किले में रह रहे लोगों को नोटिस दिए जाने के मामले में गलत तथ्य प्रस्तुत कर सदन का समय नष्ट किया, यह विशेषाधिकारों का हनन है।”

गर्ग ने यह प्रस्ताव सदन में रखा और कहा कि गत 24 फरवरी को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भरतपुर के लोहागढ़ किले में रह रहे लोगों को नोटिस दिए जाने के मामले में गलत तथ्य प्रस्तुत कर सदन का समय नष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह विशेषाधिकारों का हनन है। कांग्रेस विधायकों ने इसका विरोध किया।
जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि यह मुद्दा

सदन में गत 24 फरवरी को आया और सरकार ने तुरंत अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट मांगी और नगर निगम भरतपुर के सीओ ने एक प्रेस नोट जारी करके इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि जब किले में रहे लोगों को एक भी नोटिस जारी नहीं किया गया तो गलत सूचना को सदन में क्यों उठाया गया। उन्होंने कहा कि सदन में सदस्यों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नरेगा लोकपाल की अपील सुनने के लिये प्राधिकरण का गठन क्यों नहीं किया गया?

जयपुर, 3 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख पंचायती राज सचिव, नरेगा आयुक्त, सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर और जिला परिषद के सीईओ को नोटिस जारी कर पूछा है कि नरेगा लोकपाल के आदेश के खिलाफ अपील सुनने के लिए अपीलीय प्राधिकरण का

■ हाई कोर्ट ने पंचायतीराज सचिव, नरेगा आयुक्त तथा सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर व जिला परिषद सीईओ को नोटिस जारी किया

गठन क्यों नहीं किया गया है। इसके साथ ही, अदालत ने प्रमुख पंचायती राज सचिव को यह बताने को कहा है कि अपीलीय प्राधिकरण का गठन करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं, अदालत ने मामले में याचिकाकर्ता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिपोर्टर्स क्लैक्टिव आदि, मीडिया प्लेटफॉर्म का “नॉन प्रॉफिट” दर्जा खत्म हुआ

आयकर विभाग का तर्क है, कि, “पत्रकारिता” कोई ऐसी गतिविधि नहीं है, जिससे कोई “सार्वजनिक हित” होता है, अतः इस खोजी पत्रकारिता का स्तम्भ माने जाने वाली इन संस्थाओं को भी, इन्कम टैक्स देना होगा, और सम्भवतया “बैक डेट” से

-डॉ. सतीश मिश्रा-
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 मार्च। डिजिटल मीडिया प्रतिष्ठानों की एक “अम्बरेला बॉडी” ने सरकार के इस दावे को चुनौती दी है कि पत्रकारिता आम जनता से जुड़े उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में काम नहीं कर रही, तथा इसे “लोकतंत्र की बुनियाद के विपरीत एवं बेहद चिंताजनक बताया है।”
सरकार ने कथित रूप से, दो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन्वैस्टिगेटिव जर्नलिज्म पोर्टल “रिपोर्टर्स क्लैक्टिव” तथा कन्नड़ वैंबसाइट “फाइल” का नॉन प्रॉफिट स्टेटस कैंसल करते हुए यह दावा किया था।
डिजिपब न्यूज़ इंडिया फाउन्डेशन ने एक बयान में कहा, “इस प्रकार के दावे का उपयोग अन्य स्वतंत्र न्यूज़

■ इन संस्थाओं का कहना है, कि, 2025 में उसका गठन हुआ था, तथा उन्हें “नॉन प्रॉफिट संस्था” का दर्जा देकर आयकर से मुक्त किया था सरकार ने। पर, अब 2025 में यह सुविधा वापस ले ली गई है, क्योंकि पत्रकारिता से कुछ “सार्वजनिक हित” (पब्लिक परपस) सिद्ध नहीं होता।

आउटलैट्स को वित्तीय रूप से निशाना बनाने के लिये किया जा सकता है। अगर सरकार मानती है कि भारत सचमुच लोकतंत्र है, केवल नाम का लोकतंत्र नहीं, तो सरकार को यह आरोप वापस लेना चाहिये।
इन दोनों प्रतिष्ठानों का नॉन-प्रॉफिट स्टेटस इसलिए निरस्त किया गया, क्योंकि सरकार ने कथित रूप से यह तर्क दिया कि पत्रकारिता कोई ऐसा काम नहीं है, जिसका जनहित में कोई उद्देश्य हो। अलाभकारी समाचार प्रतिष्ठान, “द

इसे अलाभकारी कवायद के रूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।”
सोमवार को डिजिपब ने रिपोर्टर्स क्लैक्टिव पर टैक्स अधिकारियों की टिप्पणी का उल्लेख किया और कहा कि दिल्ली स्थित रिपोर्टर्स क्लैक्टिव, जो खोजी पत्रकारिता करता है, को दिये आदेश में विभाग ने कहा था कि “इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता को आगे बढ़ाना तथा क्रियान्वित करना है।..... आवेदक यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा है कि इसकी गतिविधियाँ किस तरह जनता के लिये उपयोगी तथा फायदेमंद हैं।”
“डिजिपब” ने अपने बयान में कहा, “इसका अर्थ यह हुआ कि 2021 से चल रहे सार्वजनिक चित्त पोषित गैरलाभकारी ट्रस्ट, रिपोर्टर्स क्लैक्टिव को अब टैक्स से छूट नहीं मिलेगी। जिस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की मांग

नयी दिल्ली, 03 मार्च। कांग्रेस ने आदिवासी समाज के साथ न्याय नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वन भूमि पर उनके अधिकारों को छीनकर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए विश्व आदिवासी दिवस पर

■ आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन डॉ. भूरिया ने कहा कि आदिवासियों की समस्या पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना चाहिये।
सार्वजनिक अवकाश घोषित कर इस समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन डॉ विक्रान्त भूरिया ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान व तेलंगाना 1600 मेगावाट की थर्मल परियोजनायें लगायेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल की उपस्थिति में सिंगरेनी कोलियरीज व राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में एमओयू हुआ

जयपुर, 3 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने प्रदेश में सुदृढ़ प्रसारण तंत्र एवं थर्मल और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन दूरगामी निर्णयों से राजस्थान जल्द ही देश में “ऊर्जादाता” की भूमिका में उभरेगा। उन्होंने कहा कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) तथा केन्द्र सरकार और तेलंगाना सरकार के उपक्रम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के बीच संपादित हुआ एमओयू प्रदेश में बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति की दिशा में मील का पथर साबित होगा।
शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य आयोजित

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि तेलंगाना में लगने वाली 1600 मेगावाट की परियोजनाओं में दोनों राज्यों को 800-800 मेगावाट बिजली मिलेगी।
■ एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, तेलंगाना के ऊर्जा सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, आरवीयूएनएल के सीएमडी देवेन्द्र शृंगी, सिंगरेनी कोलियरीज के सीएमडी एन. बलराम, राजस्थान के मुख्यमंत्री के सचिव आलोक गुप्ता व अन्य उच्च अधिकारी शामिल थे।
समझौता ज्ञान हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही राजस्थान सीर ऊर्जा में अपार संभावनाओं वाले राज्य के रूप में उभर रहा है। जल्द ही राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के किसानों को 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में नीतिगत निर्णय लेते हुए उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित भी कर रही है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य आयोजित समझौता ज्ञान हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित किया।

शर्मा ने कहा कि एमओयू के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाएँ तेलंगाना में स्थापित होंगी। इसमें से 800-800 मेगावाट बिजली तेलंगाना एवं राजस्थान दोनों राज्यों को मिलेगी। इसके

अतिरिक्त राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए आरवीयूएनएल ने भूमि भी चिन्हित कर ली है। इस पार्क में लगभग 6 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
इन सभी परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 22 हजार करोड़ रुपये है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 में राजस्थान द्वारा 2030 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को 17 मार्च को तलब किया

जयपुर, 3 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से संसाधनों की कमी का हवाला देकर बजरी खनन से जुड़े मामलों की जांच करने में असमर्थता जताने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही, अदालत ने

■ बजरी खनन के मामलों की जांच, संसाधनों की कमी के कारण नहीं कर पाने की सीबीआई की दलील को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया और निदेशक को व्यक्तिगत रूप से या वीसी के जरिए उपस्थित होने को कहा।
सीबीआई निदेशक को 17 मार्च को तलब किया है। अदालत ने कहा कि निदेशक व्यक्तिगत: या वीसी के जरिए अदालत में हाजिर हों। जस्टिस समीर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

चिंता से चित्त को संताप और आत्मा को दुर्बलता प्राप्त होती है, इसलिए चिंता को तो छोड़ ही देना चाहिए। -ऋग्वेद

परिसीमन - क्या, क्यों और कैसे?

डिलिमिटेड या परिसीमन आजकल चर्चा में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने डिलिमिटेड को वर्तमान स्वरूप में, दक्षिणी राज्यों के हित के विरुद्ध बताया है। इसके पूर्व कि हम इसके गुणवर्ण पर चर्चा करें, यह उपयुक्त होगा कि परिसीमन की प्रथम, इसके उद्देश्यों और इसकी प्रक्रिया का विवेचन किया जाय।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में डिलिमिटेड आयोग के गठन की बात की गई है, जो राज्यवार लोकसभा की सीटों और विधानसभा की सीटों की संख्या का निर्धारण करेगा और साथ ही उनका सीमांकन भी करेगा। यह कार्य प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किए जाने का प्रावधान था।

1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोगों का गठन किया गया जिन्होंने जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में क्रमशः 494, 522 और 543 सीटें निर्धारित कीं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन मतदाताओं की संख्या 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के

आधार पर क्रमशः 7.3, 8.4 और 10.1 लाख थी। वर्तमान की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर एक लोक सभा क्षेत्र में औसतन लगभग 18 लाख मतदाता हैं। सामान्यतया, लोकतंत्र का सिद्धांत होता है कि एक व्यक्ति का एक वोट और प्रत्येक वोट का मूल्य भी समान हो। परिसीमन आयोग ने इस सिद्धांत के आधार पर यह निर्णय लिया कि भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा सीटों के मतदाताओं की संख्या में 10 प्रतिशत तक का अंतर हो सकता था।

केवल जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का राज्यवार निर्धारण करने से यह संभावित था कि दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होता चला जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए 1973 के कानून के अनुसार लोकसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2000 तक कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग ने अपना कार्य 1976 में पूरा किया और इसी के आधार पर राज्यवार, लोकसभा की सीटें निर्धारित की गईं।

केवल जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें निर्धारित करने का परिणाम यह हुआ कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्रभावी रूप से लागू किया उन्हीं, आनुपातिक रूप से लोकसभा की सीटें कम मिलीं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1976 में संविधान में 42वाँ संशोधन किया गया। इसके माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2000 तक किसी भी राज्य की लोक सभा सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि 1991 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या तो वही रहेगी, किंतु सीटों के पुनर्समीकरण का कार्य किया जा सकता है। बाद में सीमांकन का यह कार्य 1991 की जनगणना के आधार पर नहीं करके, इसे 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया।

जनसंख्या को आधार मानकर निर्णय लेने का प्रभाव केवल लोक सभा की सीटों पर ही नहीं होता है, अपितु जनसंख्या के आधार पर ही केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों का आवंटन भी राज्यों को किया जाता है। 2011 तक तो वित्त आयोग द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर ही वित्तिय संसाधनों का आवंटन किया जाता था। पहली बार 15 वें वित्त आयोग ने 2011 की जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय फंड का रियोजू को आवंटन किया, जिससे दक्षिण के राज्यों में यह आंशिक उत्पन्न हुई कि उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले फंड में कमी आएगी।

इसका अर्थ यह निकलने लगा कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफलता पूर्वक लागू किया, जिनके प्रशासन ने अच्छा काम किया और तेजी से प्रगति की, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा कम सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार उनके राज्यों में लोकसभा की सीटें भी आनुपातिक रूप से कम हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि हम यह मान लें कि लोकसभा की कुल सीटें 543 ही रखी जाती हैं और सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर राज्यों को किया जाता है, तो उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में 80 से बढ़कर 91, मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 33, बिहार में 40 से बढ़कर 50 और राजस्थान में 25 से बढ़कर 31 हो जाएंगे। किंतु इसके साथ ही, दक्षिण भारतीय राज्यों में तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 से घटकर 31, केरल में 20 से घटकर 12, कर्नाटक में 28 से घटकर 26 और आंध्र प्रदेश में 42 से घटकर 34 रह जाएंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल चार उत्तर भारतीय राज्यों में ही लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान से 31 बढ़ जाएगी, वहीं दक्षिण के चार राज्यों में यह संख्या 26 कम हो जाएगी।

फिलहाल तो एक ही समाधान प्रतीत होता है और वह यह कि प्रत्येक राज्य की सीटों का कुल सीटों में प्रतिशत बनाए रखते हुए उनकी संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाए। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है जिसमें लगभग 105 करोड़ वोटर हैं। वर्तमान की 543 लोकसभा की सीटों को यदि 305 के लगभग बढ़ाया जाता है तो प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों में 305 की वृद्धि की जा सकती है।

इस अत्यंत असमान वृद्धि (150 की तुलना में 35) का प्रभाव यह होगा कि दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक महत्व बहुत हद तक कम हो जाएगा। यही बात दक्षिण भारत के राज्यों को परेशान कर रही है। वे चाहते हैं कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसी भी रूप में कम ना हो।

भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने अपने तमिलनाडु के दौर में यह आश्वासन तो दिया कि तमिलनाडु की सीटें कम नहीं होंगी, किंतु यह नहीं बताया कि उत्तर भारत की सीटें कितनी बढ़ेंगी? किसी राज्य का महत्व इस पर निर्भर करता है कि वहां से कुल कितने लोकसभा सदस्य हैं? यही संख्या निर्धारित करती है कि लोक सभा में किसका बहुमत होगा और कौन केंद्र में सरकार बनाएगा। यह सर्वज्ञात है कि भाजपा की अधिकांश सीटें उत्तर भारतीय राज्यों से आती हैं। किसी भी राज्य का महत्व तुलनात्मक रूप से देखा जाता है, न कि केवल संख्या के आधार पर। यदि केवल जनसंख्या को ही आधार माना जाता रहे तो यह एक प्रकार से न केवल भारत के संघीय ढांचे पर चोट होगी, अपितु राज्यों को प्रगति करने से हतोत्साहित भी करेगा। कोई भी राज्य यह नहीं चाहता कि देश की राजनीति में उसका प्रभाव एवं प्रभुत्व किसी भी दृष्टि से कम हो।

अब यह तय किया गया है कि 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा और सीटों की संख्या एवं उनकी सीमाओं का निर्धारण भी किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो उपरोक्त विवेचन अनुसार उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों का राजनीतिक महत्व एवं उनके बीच राजनीतिक संतुलन बहुत बदल जाएगा और वह पूर्णतया उत्तर भारत के पक्ष में हो जाएगा। इसी कारण, दक्षिण के राज्य परिसीमन का विरोध कर रहे हैं।

इसका एक व्यावहारिक समाधान यह हो सकता है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों की लोकसभा में जितनी सीटें बनती हैं, उतनी ही प्रतिशत बनाए रखें। सीटों की संख्या के साथ ही कौन-कौन सी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित होंगी, इसका भी निर्णय परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाये। यह उल्लेखनीय है कि परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसके सदस्य होते हैं।

भारत सरकार ने संसद के माध्यम से लोक सभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए छह तिहाई आरक्षण कर दिया है। यह आरक्षण, परिसीमन से तय होना चाहिए। परिसीमन तब होना जब जनगणना हो जाएगी। एक प्रकार से यही कहावत सही होती दिखाई दे रही है कि 'न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी'।

1901 के बाद लगातार जनगणना हर 10 वर्षों में हो रही थी किंतु पहली बार 2021 वाली जनगणना 2025 तक भी नहीं हो पाई है और यह संभावना है अब यह 2026 में हो। जनगणना में भी एक पंच यह फंसा हुआ है कि जातिगत जनगणना हो अथवा नहीं? जहां विपक्षी दल, कांग्रेस के नेतृत्व में एक मत से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, वहीं भाजपा इसके पक्ष में दिखाई नहीं देती। इस विवादास्पद मुद्दे का समाधान हुए बिना जनगणना भी समय पर होती हुई दिखाई नहीं देती। जब जनगणना ही नहीं होगी तो फिर परिसीमन भी टल जाएगा और परिणाम स्वरूप, महिला आरक्षण भी एक प्रकार से केवल फाइलों में बंद होकर रह जाएगा।

कुल मिलाकर, परिसीमन का पूरा मुद्दा लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट और प्रत्येक वोट का एक मूल्य पर टिका है तथा दूसरी ओर इसे भारत के संघीय ढांचे पर प्रहार बताया जा रहा है। यदि संघीय ढांचे को वरीयता दी जाए तो दक्षिण भारतीय राज्यों को भी पूर्व में मिली हुई वरीयता और उनकी हिस्सेदारी को बनाए रखा जाना चाहिए। वहीं, केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने पर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इस जटिल प्रश्न का उत्तर क्या मिलेगा यह तो समय ही बताएगा। भारत, क्योंकि कई विविधताओं वाला देश है, इसका समाधान भी सबको महत्वकांक्षाओं का ध्यान रखे बिना संभव नहीं होगा।

फिलहाल तो एक ही समाधान प्रतीत होता है और वह यह कि प्रत्येक राज्य की सीटों का कुल सीटों में प्रतिशत बनाए रखते हुए उनकी संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाए। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है जिसमें लगभग 105 करोड़ वोटर हैं। वर्तमान की 543 लोकसभा की सीटों को यदि 30% के लगभग बढ़ाया जाता है तो प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों में 30% की वृद्धि की जा सकती है। यह एक व्यावहारिक समाधान तो है लेकिन क्या यह सभी राज्यों को स्वीकार्य होगा एवं क्या वर्तमान केंद्र सरकार इसको होने देगी? यह लिखना भी उपयुक्त होगा कि केंद्र में सत्ताधारी दल भाजपा का मुख्य आधार उत्तर भारत में है। वह इसीलिए यह चाहती है कि उत्तर भारत के राज्यों का कुल प्रतिनिधित्व लोकसभा में इतना हो जाय कि दक्षिण भारतीय राज्य किसी प्रकार की चुनौती देने की स्थिति में भी न रहे।

कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जहां परिसीमन (यानि डिलिमिटेड) की असम संभावनाएं हैं वहीं चुनौतियां भी अपार हैं तथा साथ ही, जहां यह संवैधानिक रूप से आवश्यक है, वहीं इसे लागू करना कठिन भी। अब, यह सत्ता धारी दल की राजनीतिक परिपक्वता पर निर्भर करता है कि वह इसका समाधान कैसे निकाल पाता है।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



राजेन्द्र राठौड़

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका प्रदान करता है और देश की जीडीपी में इसकी 18-20 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। देश का कृषि क्षेत्र देश की लगभग आधी जनसंख्या को रोजगार देता है। भारत ने 2023-24 में 332.2 मिलियन टन का रिकॉर्ड कुल अनाज उत्पादन हासिल किया जो भारतीय किसानों के खेती के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण है। देश में हरित क्रांति के बाद से कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए कोटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया लेकिन समय के साथ इनके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। ये कोटनाशक न केवल मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालते हैं। हाल के वर्षों में जैविक खेती की ओर बढ़ते झुकाने ने इस विषय को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

भारत में 1950 में कोटनाशकों का उपयोग लगभग गायब था, लेकिन वर्ष 2023-24 तक यह खपत बढ़कर 255.54 हजार टन हो गई है। यह वृद्धि कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता

को दर्शाती है लेकिन साथ ही इसके नकारात्मक प्रभावों को भी उजागर करती है। एनवीएमएट रिकॉर्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार 12 प्रमुख फल और सब्जियों में कोटनाशकों की खतरनाक मात्रा पाई गई है। इनमें भिंडी, टमाटर, मिर्च, पालक, शिमला मिर्च, गोभी, आम, अंगूर, सेब, केले, पपीता, स्ट्रॉबेरी आदि शामिल हैं।

कोटनाशक फसलों को कोटों और बीमारियों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन वे उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करते हैं जो उनका छिड़काव तथा रखरखाव करते हैं। कोटनाशकों के बढ़ते उपयोग से कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जहरीले रसायनों के निरंतर सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है वहीं कोटनाशकों के अवशेष लिबर को प्रभावित कर फेटी लिबर और हेपेटाइटिस जैसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इन जहरीले तत्वों के संपर्क में आने से सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं पर इनका विशेष रूप से खतरनाक प्रभाव डालता है जिससे गर्भस्थ शिशु में जन्मजात विकृतियों की संभावना बढ़ जाती है। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों में इनका प्रभाव अधिक देखा जाता है जहां सुरक्षात्मक उपायों की कमी के कारण जोखिम और बढ़ जाता है।

कोटनाशकों का पर्यावरण, विशेष रूप से जैव विविधता पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब इनका अत्यधिक या अनुचित उपयोग किया जाता है तो ये रसायन मिट्टी, जल स्रोतों और वायु को प्रदूषित कर देते हैं। कृषि क्षेत्रों में किए गए छिड़काव से कोटनाशक अक्सर नदियों, झीलें और महासागरों तक पहुंच जाते हैं जिससे

जल प्रदूषण बढ़ता है और जलीय जीवन प्रभावित होता है। ये केवल लक्षित कोटों को नहीं मारते बल्कि लाभकारी जीवों जैसे यमुमविक्रियों, तितलियों और प्राकृतिक परागणकर्ताओं की आबादी को भी नुकसान पहुंचाते हैं जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है।

लागातार कोटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की जैव विविधता नष्ट हो रही है, जिससे उसकी उर्वरता में गिरावट आ रही है। इनका अत्यधिक उपयोग लाभकारी कोटों को खत्म कर देता है जिससे कोटों के प्राकृतिक नियंत्रण में बाधा उत्पन्न होती है और खेती में जैविक संतुलन बिगड़ता है। इससे खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता और पोषण स्तर भी प्रभावित होते हैं। इसलिए जैविक खेती और प्राकृतिक कोट नियंत्रण उपायों को अपनाना एक सतत और सुरक्षित समाधान हो सकता है।

केंद्र सरकार ने कोटनाशकों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अत्यधिक खतरनाक कोटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने और जैविक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। 2015 में शुरू की गई सांघल हेल्थ कार्ड योजना के तहत मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है और किसानों को उर्वरकों व कोटनाशकों के संतुलित उपयोग की सलाह दी जाती है जिससे जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है तथा जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसान कवच की शुरुआत करना किसानों को कोटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से

बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। उन्नत फेनैक्रिक तकनीक युक्त यह अभिनव सूट किसानों की सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पहल के साथ-साथ सरकार जैव कोटनाशकों के अपनाने को बढ़ावा देते हुए रासायनिक कोटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। ये प्रयास किसानों और पर्यावरण दोनों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ कृषि भविष्य बनाने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

एशिया के सबसे प्रदूषित नालों की सूची में शामिल बृहदा नाला में लुधियाना की औद्योगिक इकायों के साथ-साथ शहर के सीवरज का प्रदूषित पानी बिना साफ किए राजस्थान के 22 जिलों को पेयजल देने वाली इंदिरा गांधी नहर में सोधा डाला जा रहा है। इस जल का उपयोग सिंचाई में होने से खेतों की उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। श्रीगंगा नगर और हनुमानगढ़ के किसानों ने इस गंभीर समस्या के खिलाफ आवाज उठाई थी और नाले को मिट्टी से पाटने की घोषणा भी की थी। वहीं सीवरज के गंदे पानी में उगने वाली सब्जियां अत्यधिक विषैली होती हैं क्योंकि ये जल में मौजूद रसायनों और भारी धातुओं को अवशोषित कर लेती हैं। यही सब्जियां जब बाजार में पहुंचती हैं तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाती है। इसका समाधान जैविक खेती को बढ़ावा देना और जलशुद्धिकरण की प्रभावी व्यवस्था करना है। कोटनाशकों के प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्त कानूनों के साथ टिकाऊ कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा देना जरूरी है। सरकार ने रसायन-मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जैव कोटनाशकों और जैविक खेती संबंधी कई पहल शुरू की हैं। विभिन्न फसलों

में कोटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, खेती को लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जैव नियंत्रण का उपयोग एक महत्वपूर्ण समाधान साबित हो सकता है।

रासायनिक कोटनाशकों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए जैविक खेती आवश्यक हो गई है। इसमें हरी खाद, वर्मीकम्पोस्ट, फसल चक्र, मिश्रित फसल प्रणाली, नीम तेल, जैविक स्प्रे, गोबर और केंचुए की खाद जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भारत में जैविक कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार और किसानों को मिलकर प्रयास करने होंगे। इसके लिए किसानों को जैविक खेती की तकनीकों पर प्रशिक्षण देना, आर्थिक सहायता और सब्सिडी प्रदान करना आवश्यक है। साथ ही जैविक उत्पादों के लिए विशेष बाजार उपलब्ध करना जरूरी है जिससे किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके।

कोटनाशकों का अत्यधिक उपयोग न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बनाता जा रहा है। जैविक खेती प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करती है। हालांकि प्रारंभ में जैविक खेती की पैदावार कम हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह अधिक लाभकारी साबित होती है। जैविक खेती से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिलेगा, इसलिए इसे अपनाना समय की मांग है। हमें स्वयं भी जागरूक होकर जैविक उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ जीवन और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकें।

-राजेन्द्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष

12 भाई-बहनों समेत पांचू गांव के 18 युवाओं ने साइक्लिंग में पहचान बनाई

बीकानेर, (निर्सं) पांचू के पन्नाराम तर्द के परिवार की आज समाज ही नहीं देश में अलग की पहचान है। यह पहचान उनके पोते-पोतियों में साइक्लिंग द्वारा कमाई है। इन भाई-बहनों ने साइक्लिंग में नेशनल और इंटरनेशनल तक पहचान बनाई है। इन 12 भाई-बहनों में पांचू तो सगे भाई हैं। इन्होंने खेल के जरिये न केवल नेशनल गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉज मेडल जीते बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई।

साइक्लिंग के माध्यम से ही इनमें से कोई आर्मी तक पहुंचा तो कोई रेलवे में। इनमें से दो भाई को भारतीय टीम को और से भी खेले। इन्हें साइक्लिंग में इतना नाम कमाते देख गांव के छह युवाओं ने भी साइक्लिंग प्रतियोगिताओं में भाग्य आजमाया गांव के 18 खिलाड़ियों में आठ महिला

खिलाड़ी और 10 पुरुष साइक्लिस्ट हैं। गांव के दिनेश तर्द ने 2014 में बीकानेर में साइक्लिंग शुरू की। कुछ समय ट्रेनिंग लेने के बाद अगले ही साल हुई साइक्लिंग नेशनल प्रतियोगिता में दिनेश ने पदक जीता। सुरेश, मनोज, राजूराम और ब्रिमेश ने भी साइक्लिंग शुरू कर दी। अब तक दिनेश ने 15 नेशनल पदक जीत लिए, इनमें तीन गोल्ड और दो सिल्वर एशिया पर में एक सिल्वर और ब्रॉज मेडल भी अपनी झोली में डाले। आर्मी को साइक्लिंग टीम के कोच राजूराम तर्द ने बताया कि उन्होंने पांच साल तक आर्मी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। 11 खिलाड़ियों में दिनेश ने उनकी भूमिका अहम रहती। आर्मी की सातों कमांडो के बीच हुए कंपीटिशन के बाद उनका चयन नेशनल टीम में हुआ। उनके साथ दो अन्य खिलाड़ी भी

- इन 12 भाई-बहनों में पांचू तो सगे भाई हैं, इन्होंने खेल के जरिये नेशनल गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉज मेडल जीते हैं
- गांव के 18 खिलाड़ियों में आठ महिला खिलाड़ी और 10 पुरुष साइक्लिस्ट हैं

नेशनल टीम में चुने गए। उस समय उन्होंने वेस्टन आर्मी कमांड, चंडीगढ़ में इंटर आर्मी में पदक जीता। अब बीकानेर में साइक्लिंग में दिनेश ने पदक जीते। गांव के 18 खिलाड़ियों में आठ महिला खिलाड़ी और 10 पुरुष साइक्लिस्ट हैं।

पॉंचू के तर्द परिवार ने साइक्लिंग में 12 नेशनल खिलाड़ी दिए हैं। इनमें से दो भाइयों ने अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। तर्द परिवार के ब्रिमेश, राजूराम, दिनेश, सुरेश और मनोज तर्द को सगे भाई हैं। इनमें दिनेश और मनोज ने अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। वहीं राजूराम आर्मी में साइक्लिंग खिलाड़ी और

जौत लिया। पांचू में एक ही परिवार के 12 खिलाड़ियों को पदकवीर बनाने वाली गुरुदेव साइक्लिंग एकेडमी की एक महिला खिलाड़ी ने 21 से 27 फरवरी तक मलेेशिया के निलाई शहर में हुई एशियन टैक साइक्लिंग में टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। एकेडमी के अंतरराष्ट्रीय कोच किशन पुरोहित ने बताया कि हमारी एकेडमी ने इन दिनों 150 खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारतीय साइक्लिंग टीम में अधिकांश खिलाड़ी बीकानेर में ही तैयार होते हैं। अब तक हमने कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। हमने अभी तक 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। इसमें कोरोना काल के बाद 20 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं।

सिलिका सैंड ले जा रही ओवरलोड 16 गाड़ियां पकड़ी, 35 लाख का जुर्माना लगाया

बीकानेर, (निर्सं)। खान निदेशालय की विजिलेंस टीम ने बीकानेर की खानों से ओवरलोड भरकर निकली सिलिका सैंड की 16 गाड़ियां श्रीगंगा नगर में पकड़ी हैं। जिन पर करीब 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रवने में वजन 20 टन दर्ज था, जांच में 70 टन खनिज मिला।

बीकानेर से बजरी और सिलिका सैंड की सैकड़ों गाड़ियां रोजाना श्रीगंगा नगर, हनुमानगढ़, चूरू, हरियाणा-पंजाब सहित अनेक स्थानों पर जाती हैं। खानों से खुलेआम ओवरलोड गाड़ियां भरकर निकाली जा रही हैं और उनके रज्जे में वजन कम बताया जा रहा है। इसकी शिकायत खान एवं भूविज्ञान विभाग के उदयपुर स्थित निदेशालय को मिली तो वहां से गुपचुप तरीके से विजिलेंस की टीम भेजी गई। एमई प्रकाश माली को

देखरेख में इस टीम ने बीकानेर की खानों से सिलिका सैंड की रज्जा पर बेखौफ निकली 16 ओवरलोड गाड़ियों को श्रीगंगा नगर में पकड़ा है। इन गाड़ियों में विभागीय एम्पैनेल्ड तुलाई यंत्र से 20 टन खनिज बताया गया है, लेकिन वास्तव में 50 से 70 टन खनिज भर रखा है।

विजिलेंस टीम ने करीब 35 लाख रुपए की शास्ती तय की है। निदेशालय से आई विजिलेंस टीम की कार्रवाई से ओवरलोड खनिज निर्गमन करने वालों में हड़कंध मचा है। खनिज बजरी और सिलिका सैंड देखने में एक जैसे ही हैं। जांच की जाएगी कि गाड़ियों में कहीं सिलिका सैंड के नाम पर बजरी तो नहीं भरी रखी है। टीम ने सैपल लिए हैं जिसकी प्रयोगशाला में जांच होगी। अगर जांच में बजरी निकली तो सैपदा की शर्तों का

उल्लंघन मानते हुए संबंधित खान मालिकों पर कार्यवाही होगी और पर्यावरण शास्ती भी अलग से वसूली जाएगी। खान निदेशालय ने जिन खानों से खनिज का निर्रगम किया गया है, वहां जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा विभागीय एम्पैनेल्ड तुला यंत्र और इंआरसीसी टेकेदार की ओर से काटी गई रसीदों की भी जांच की जाएगी।

राशिफल मंगलवार 4 मार्च, 2025



पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् 2081, भरणी नक्षत्र रात्रि 2:38 तक, ऐन्द्रयन योग रात्रि 2:06 तक, बालव करण दिन 3:17 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।
ग्रहस्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।
आज ज्वालामुखी योग दिन 3:17 तक है। रवियोग सायं 6:41 तक है, पुनः रात्रि 2:38 से आरम्भ होगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 2:38 से आरम्भ होगा।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:45 से 11:12 तक, लाभ-अमृत 11:12 से 2:05 तक, शुभ 3:32 से 4:95 तक।
राहुकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:52, सूर्यास्त 6:26

- | | | |
|---|---|---|
| <p>मेष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।</p> | <p>सिंह
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।</p> | <p>धनु
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।</p> |
| <p>वृष
आर्थिक कारणों से परेशानी हो सकती है। धन हानि हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।</p> | <p>अश्वि
चन्द्रमा कष्टम भव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बने कार्य बिगड़ सकते हैं। आज आर्थिक मामलों से परेशानी हो सकती है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।</p> | <p>मकर
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।</p> |
| <p>मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।</p> | <p>तुला
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।</p> | <p>कुंभ
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में उचित परामर्श मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।</p> |
| <p>कर्क
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगे लगेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।</p> | <p>वृश्चिक
स्वास्थ्य में सुधार होगा। अस्त-व्यस्त दिवसों में उचित चिन्ता व्यक्तियों होने लगेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।</p> | <p>मीन
आर्थिक कार्यों से अटके हुए कार्य बनने लगेगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।</p> |

फूलों की होली के साथ रास लीला

करौली। स्टेट टाइम के शिक्षाविद मास्टर छुट्टन लाल कृष्ण प्यारी सारस्वत निवासी चैबेपाडा करौली कि 31 वीं पुण्य स्मृति में आयोजित भव्य रासलीला के सोमवार को तीसरे दिन राधा मदन मोहन जी महाराज के मंदिर में फूलों के होली कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोमवार को कार्यक्रम के दौरान भगवान के महारास मयूर नृत्य, भगवान कि विभिन्न झांकियां के साथ राधा जी के साथ भगवान की श्याम सगाई का मंचन भावपूर्ण स्वरूपों द्वारा किया गया रासलीला के दौरान मयूर नृत्य और भगवान के महारास को देखकर लोग भावविभोर हो गए रासलीला का यह आयोजन उनके परिवार द्वारा तीन दिवस का किया गया जिसका सोमवार को फूलों कि होली, गुलाल की होली और होली के गीतों के साथ संपन्न हुआ अनोखे पुत्र डॉ. विष्णु चंद्र शर्मा जो राज्य वन सेवा के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी हैं ने बताया कि यह आयोजन उनके माता-पिता के आशीर्वाद और श्री मदन मोहन जी महाराज कि कृपा से ही संभव हो सका है।

सनातन संस्कृति से साक्षात्कार कराने को लगेंगी विहिप की संस्कारशालाएँ

भरतपुर (निस)। विहिप सेवा विभाग जयपुर प्रांत प्रमुख नरेश खण्डेवाल ने बताया कि संस्कारों की पाठशाला, संस्कारशाला में किशोरों को पुस्तकीय जानकारी देने के साथ ही सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए भारतीय संस्कार दिया जाता है। उन्हें भारतीय पर्व, व्रत, त्योहारों की ऐतिहासिकता व पौराणिकता की जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही उसकी महत्ता भी समझाई जाती है। देश के गौरव महापुरुषों, वीरगणों के जीवन और उनकी वीरगाथा से परिचित कराकर उनमें राष्ट्रभक्ति के भाव को जागृत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों-किशोरों को पुस्तकीय जानकारी तक सीमित न रखते हुए उन्हें ज्ञानार्जन कराना है। सनातन संस्कृति की जागृत चेतना के भाव की सतत स्थापना और समाज में समरसता को बढ़ाने को विश्व हिंदू परिषद संस्कारशाला अभियान को नई धार देने जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ से उत्पन्न जागृत चेतना से भावी पीढ़ी को साक्षात्कार करने और उन्हें सनातन शिक्षा देने के

भरतपुर (निस)। सडक सुरक्षा समिति की बैठक सोमवार को जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित विभागों को आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने में विभागीय दायित्व निर्वहन हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर ने कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के महारास को देखकर लोग भावविभोर हो गए रासलीला का यह आयोजन उनके परिवार द्वारा तीन दिवस का किया गया जिसका सोमवार को फूलों कि होली, गुलाल की होली और होली के गीतों के साथ संपन्न हुआ अनोखे पुत्र डॉ. विष्णु चंद्र शर्मा जो राज्य वन सेवा के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी हैं ने बताया कि यह आयोजन उनके माता-पिता के आशीर्वाद और श्री मदन मोहन जी महाराज कि कृपा से ही संभव हो सका है।

उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिये ऐसे स्थानों को चिन्हित कर ऐलिवेटेड रोड बनाये जाने के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये। उन्होंने सेवर से सारस चौराहे तक 8 किलोमीटर लम्बाई की ऐलिवेटेड रोड के प्रस्ताव को इस तरह तैयार करने के निर्देश दिये कि मलाहा पुलिया का उपयोग यथावत हो सके, प्रस्ताव बनाते समय ब्लैक स्पॉट का विशेष ध्यान रखा

■ संस्कारशालाओं में व्रत, त्योहार व राष्ट्रभक्ति संग दिए जा रहे भारतीय संस्कार। विहिप सेवा विभाग जयपुर प्रांत प्रमुख नरेश खण्डेवाल ने दी जानकारी

उद्देश्य से विहिप गांव-गांव, शहर-शहर संस्कारशाला अभियान चलाएगी। यह निर्णय विहिप सेवा विभाग की मुंबई में हालिया संपन्न सेवा विभाग अखिल भारतीय टूरटी एवं समिति के पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया। यह भी तय हुआ कि यह बैठक अब हर पांच वर्ष में आयोजित की जाएगी, जिसमें पांच वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा व सेवा कार्यों की योजना बनाई जाएगी। विश्व हिंदू परिषद 4 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सनातन संस्कार से परिचित करने के लिए आंगनवाडी की तंत्र पर संस्कारों की पाठशाला और

सड़क हादसे वाले स्थानों को चिन्हित किया जाये : डॉ. अमित यादव

■ बैठक में सभी संबंधित विभागों को आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने में विभागीय दायित्व निर्वहन हेतु निर्देशित किया गया

जाये। उन्होंने मलाहा पुलिया से शीशम तिराहे तक सर्विस रोड बनाने हेतु निर्देशित किया जिससे मैरिज होमों पर समारोहों के दौरान होने वाली भीड़ से यातायात बाधित न हो और न ही दुर्घटना की आशंका रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर आवाग षणुओं को पकडकर आसपास की गौशालाओं अथवा चारागाह भूमि चिन्हित कर तारबंदी करते हुये आवाग षणुओं को पहुँचाएँ जिससे पशुजनित दुर्घटना रोकी जा सके। उन्होंने केवलादेव घने के पास

उच्च क्वालिटी का साइन बोर्ड लगवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास सरकारी भूमि पर लगी दुकानों द्वारा किये गये अतिक्रमण को पुलिस से समन्वय कर हटवायें और यदि किसी तरह के बूथ की स्वीकृति जारी कर रखी है तो उसे संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही कराते हुये निरस्त करे। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित डहरा मोड, उँचा नगला एवं हलौना पर पलाईओवर बनाने की डीपीआर बनाकर शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रभावी पेट्रोलिंग करते हुये सडक किनारे खडे होने वाले वाहनों के खिलाफ चालान की कार्यवाही कर स्थानीय पुलिस को सूचना देकर एफआईआर भी कराये। उन्होंने एनएचआई को राष्ट्रीय राजमार्ग पर घनी आबादी क्षेत्र, अस्पताल, स्कूल व अन्य जनिहित स्थानों के साईनेज प्रदर्शित करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि रोड किनारे झुके हुये

मुआवजे दिलाने की मांग

हलौना। गत दिन अति वृष्टि और ओलावृष्टि की वजह से सम्पूर्ण क्षेत्र में बाबाई हुई किसानों की सरसों और गेहूँ की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर कस्बा हलौना उप तहसील में किसान नेता इन्दल सिंह जाट के नेतृत्व में किसानों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया। किसान नेता इन्दल सिंह जाट ने नायब तहसीलदार लखन गुप्ता को प्रस्तत किया। ज्ञापन में कहा कि अत्याधिक ओलावृष्टि की वजह से किसानों के सपने टूट गये है, किसानों की महत्वपूर्ण सरसों, गेहूँ की पक्की तैयार खेड़ी फसल चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि यही फसल किसान का सहारा होती है। उन्होंने जिला कलक्टर को भेजे ज्ञापन में शीघ्र सवं करारकर किसानो को फसल नुकसान का वाजिव मुआवजा देने तथा किसानों का कर्जा माफ करने की माँग की। नायब तहसीलदार ने ज्ञापन को आगे भेजने तथा आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही। ज्ञापन देने बालो में बलदेव सिंह नगला धरसोनी, चन्द्रप्रकाश सोलंकी हलौना, वासुदेव गुप्ता पूर्व सरपंच, रामकिशन सुवेदर नगला कपान, चेताराम खटीक, सहित अनेक किसानों ने हिस्सा लिया।

पेड़ों के निस्तारण की सूचना उच्चाधिकारियों को दे जिसेसे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने खानुआ ब्रिज के पास सडक पर आ रहे पानी के लिये एनएचआई से समन्वय कर कार्य पूर्ण कराने तथा खानुआ में जलभराव का निस्तारण व साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं शहर में संचालित मैरिज होमों पर पार्किंग व्यवस्था एवं विवाह समारोह आदि में कॉमर्सियल सिलेण्डर ही उपयोग करने हेतु संचालकों को सूचित करें जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त कलक्टर शहर राहुल सैनी, सीओ सिटी पंकज यादव, जिला परिवहन अधिकारी अभय मुद्गल, अधीक्षण अभियन्ता सावित्रि सहित एनएचआई के अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक

भरतपुर (निस)। जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई जिसमें सभी विभागों को बजट घोषणाओं के कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने कहा कि सभी विभाग बजट घोषणाओं की क्रियाविधि को गति देते हुये नवीन कार्यों की डीपीआर टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करते हुये विकास कार्यों को समय पर पूरा करें जिससे विकास कार्यों का लाभ आमजन को मिल सके। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के लक्ष्यों के अनुरूप सभी विभाग टीम भावना के साथ कार्य करते हुये जिले को अठाणी पायदान पर रखें।

उन्होंने विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में पात्र लोगों को लाभान्वित करते हुये विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा कराने के निर्देश दिये। उन्होंने बजट घोषणाओं के ऐसे कार्य जो अभी तक शुरू नहीं किये गये हैं, ऐसे कार्यों पर त्वरित कार्यवाही करते हुये शीघ्र शुरू करायें तथा प्रगतिरत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने सडक, बिजली, पानी

आठ दिन की हडताल के बाद मण्डी में काम शुरू

गंगापुर सिटी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के तत्वाधान में कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करने सहित 41 मांगों को लेकर चल रही हडताल के समाप्त होने के साथ ही नई व पुरानी अनाज मण्डी में रौनक लोट आई। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों की 8 दिन की हडताल समाप्त होते ही व्यापारियों ने खरीद फरोख्त को। संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रहलाद मेठी और मंडी समिति अध्यक्ष गोविंदप्रसाद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर में संघ पदाधिकारियों और सरकारी मंत्रियों के बीच बैठक में आश्वासन मिलने के बाद हडताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। सोमवार को मंडी सामान्य दिनों की तरह खुली। किसान गेहूँ, सरसों और चना बेचने के लिए पहुँचे। लंबे समय तक मंडी बंद रहने के कारण बड़ी संख्या में किसान एक साथ आए। दोपहर 2 बजे के बाद कृषि जिंसाँ की नीलामी शुरू हुई। मंडी में हडताल से पहले रोजाना 2 से 3 हजार कट्टे नई सरसों की आवक होती थी।

सार-समाचार दहेज प्रताडना का आरोपी पकड़ा

गंगापुर सिटी। पुलिस ने दहेज प्रताडना के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निदेशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। उर्देई मोड थाना पुलिस ने मामला संख्या 115/2०23 में कॉछिन आरोपी मानपुर निवासी पंकज कुमार बैरवा (37) को गिरफ्तार किया। उस पर धारा 498ए, 4०6, 323, 12०बी आईपीसी के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 4 के तहत मामला दर्ज था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजोर और वृत्ताधिकारी संतराम मौना के सुपरविजन में थानाधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की। टीम में कॉन्स्टेबल अकलेश, राजाराम, ब्रह्मसिंह, वीरेंद्र सिंह और वीरेंद्र कुमार शामिल थे। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है।

कन्हैया दंगल का आयोजन

करौली। गांव झारेडा सपरे वाले बाबा के सानिध्य में खारी बलू हनुमान जी के स्थान पर कन्हैया दंगल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम से जुड़े टीना मीणा ने बताया कि कन्हैया दंगल में दादनपुर, नांगल, मौना बडौदा, बूकना सपोटरा कि कन्हैया पार्टीयों ने अपनी प्रस्तुतिया दी सभापति राजेश कुमार मौना ने बताया कि कन्हैया पार्टी ने गोवर्धन कि कथा दादनपुर कि पार्टी ने बाणासुर कि कथा, मौना बडोदा कि पार्टी ने शिखण्डी के जन्म कि कथा, बूकना कन्हैया पार्टी ने भक्त पूरणमल कि कथा की अपने शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत किया। दंगल में कन्हैया पार्टीयों ने पौराणिक और धार्मिक कथाओं कि प्रस्तुति दी। कन्हैया पार्टीयों के मेडियाओ का साफा बंधन कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर आसपास के गांवों के लोगों ने प्रस्तुतियों का आनंद लिया। और गायक पार्टीयो कि होसला अफजाई कि।

रात्रि चैपाल कार्यक्रम जारी

करौली। जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने मार्च 2025 के लिये रात्रि चैपाल कार्यक्रम जारी किया। उन्होंने बताया कि आज मंगलवार को सांय 6:00 बजे से श्रीमहावीरजी पंचायत समिति की ठाम पंचायत सनेट, 11 मार्च मंगलवार को सांय 6:00 बजे से करौली पंचायत समिति की ठाम पंचायत कैलादेवी, 19 मार्च बुधवार को सांय 6:00 बजे से हिण्डौन पंचायत समिति की ठाम पंचायत धंगो, 25 मार्च मंगलवार को सांय 6:00 बजे से टोडाधीम पंचायत समिति की ठाम पंचायत किरवाडा, व 27 मार्च गुरुवार को सांय 6:00 बजे से सपोटरा पंचायत समिति की ठाम पंचायत डाबर में रात्रि चैपाल आयोजित कर जन समस्याएँ सुनी जायेगी और मौके पर अधिक से अधिक परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के साथ समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिये।

अवैध देशी कट्टा आरोपी पकड़ा

भरतपुर (निस)। एक अवैध देशी कट्टा सहित आरोपी दिलीप को गिरफ्तार किया। स्थायी वारंटो योगेश कुमार उर्फ योगी को जेल भेजा। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छवा के निदेश अनुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भरतपुर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त शहर भरतपुर के मार्गदर्शन में मदनलाल मौना थानाधिकारी थाना मधुराट के नेतृत्व में टीम बनाकर अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही के दौरान राधा किरान एएफआई ने मय जापा के दिलीप पुत्र रामखिलाडी जाति ब्राह्मण उम्र 22 साल निवासी लखनपुर थाना वरु को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 अवैध देशी कट्टा 315 बोर को बरामद किया गया है।

चैन सिंह मीणा जिला अध्यक्ष नियुक्त

करौली, (नि.सं.) राजस्थान कांठस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के अनुमोदन से राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सीबी यादव ने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। जिसमें राजीव गांधी पंचायती राज संगठन करौली के जिला अध्यक्ष पद पर चैन सिंह मीणा लोलोटी को नियुक्त किया है इनकी नियुक्ति पर कांठस पार्टी करौली के पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं पूर्व पार्षद मजीद खान, प्रभाव, उदय सिंह, मंगू प्रजापत सहित अनेको कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सीबी यादव का आभार व्यक्त किया है।

पानी की समस्या, भाजयूमो ने अपसरों को बताया

गंगापुर सिटी। शहर में चल रही पानी की समस्या को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नागेश लोढी के नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश दुबे भाजयूमो के जिला महामंत्री अतुल शर्मा और जिला मंत्री अशोक सैनी व कार्यकर्ता जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता

रामकेश मीणा से उनके कार्यालय में जाकर मिले और शहर में पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं होने पर जनता को हो रही परेशानी को लेकर नाराजगी जताई। नागेश लोढी ने कहा कि अभी तो सदी का मौसम है आगामी दिनों में गर्मी आएगी इसके लिए आपके पास

क्या योजना है पानी की अव्यवस्था से जनता में सरकार की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड रहा है। पूर्वी राजस्थान के लिए भागिरीध का कार्य करने वाले कर्मयोगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राज में गंगापुर की जनता पानी की समस्या से ग्रसित नहीं होनी चाहिए।

नागेश लोढी ने अधिशापी अभियंता से कहा कि आप शहर में पानी की सुचारु आपूर्ति करने के लिए योजना बनाए और योजना की पूर्ति के लिए यदि उच्च स्तर पर कोई बर्ता करनी या वित्तीय स्वीकृति दिलवानी है तो मैं शहर के जनता के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी से बात करूंगा और उनसे

निवेदन करूंगा कि गंगापुर सिटी भीषण पेयजल समस्या से अनेकों साल से जूझ रहा है और राजस्थान के भगीरथ सं आशा है। जिलाध्यक्ष नागेश लोढी ने दूरभाष पर एडिशनल चीफ इंजीनियर सुरेंद्र शर्मा से बात कर उनसे हर साल बरसात में चंबल परियोजना के पानी के पंप चंबल नदी डूबने और बरसात में लोगों को पानी की कमी को लेकर बात की जिस पर एडिशनल चीफ इंजीनियर सुरेंद्र शर्मा और रामकेश मीणा ने नागेश लोढी और भाजपा कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि पानी के पंप डूबने की समस्या का भी इस बार कोई समाधान दूढ लिया जाएगा और जल्दी ही गंगापुर में रोजाना नलो से पानी देने का आश्वासन दिया।

होली मिलन समारोह का आयोजन

हिंडौन सिटी। शहर के महावा रोड स्थित एक मैरिज होम में राजपूत सभा की ओर से बीती रात होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में समाज की उन प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में वचस्व हासिल कर समाज का नाम रोशन किया है। इस दौरान वक्ताओं ने समाज के लोगों से कुशलियों को त्यागकर राजनीति के क्षेत्र में आगे आने की बात कही।

राजपूत सभा हिंडौन के संरक्षक शिशुपाल सिंह जादौन, अध्यक्ष सत्यस्वरूप सिंह जादौन ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि गिरांज सिंह मलिंगा थे। इसके अलावा जिलाध्यक्ष अजय सिंह, दीपक नरुका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केसर सिंह नरुका, भाजपा जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन, सीमा जादौन, जयेंद्र सिंह, नरेन्द्र सिंह, ऊधो सिंह, रमेश सिंह पिचानीत, नरथू सिंह राजावत सहित

प्रमुख लोग मौजूद रहे। भाजपा के नवनि्युक्त जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह, सात साल की उम्र में राज्यस्तरीय घुडसवारी प्रतियोगिता में कई मेडल प्राप्त करने वाली करौली की धानवी सिंह सहित अन्य लोगों का सम्मान किया गया। वक्ताओं ने शिक्षा, खेल, व्यापार में अन्य समाजों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की सलाह दी। साथ ही कहा कि आगामी चुनावों में राजपूत समाज भी अपने प्रत्याशी उत्तराणा यही नहीं राजपूत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। सात साल की धानवी ने खुज और पुंजी में भेदभाव नहीं करते हुए खेलों में भी बेटियों को आगे आकर अवसर देने की बात कही। संरक्षक शिशुपाल सिंह जादौन व कैप्टन नरोत्तम सिंह ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने, कुशलियों से समाज को दूर रखने और संगठित रहने पर बल दिया। समारोह का मंत्र संचालन नरेन्द्र सिंह जादौन व रामचंद्र सिंह ने किया।

दुकान में आग पर दुख जताया

भरतपुर, (निस)। जिला व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष संजीव गुप्ता और जिला महामंत्री नरेन्द्र गोयल ने गुजरात के सूरत में शिव शक्ति मार्केट में कपड़ों की दुकान व गोदामों में लगी भीषण आग पर दुख प्रकट करते हुए अपनी संवेदना प्रकट की है। व्यापार महासंघ ने कहा कि इस भीषड अनिर्कांड में राजस्थान के व्यापारी वंधुओ का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ

है वह पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं पूर्णतया सडक पर आ गए हैं। व्यापार महासंघ के जिला महामंत्री नरेन्द्र गोयल ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी से फोन पर वार्ता कर गुजरात के राजस्थानी व्यापारियों को सहयोग की मांग की। सुनील सिंघी ने बताया कि वह इस विषय को लेकर सक्रिय है और शीघ्र व्यापारियों को सहायता दिलाई जाएगी।

आपके सूझबूझ से उठाए गए कदम

आपके सुखद भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं



एनआईसी का

निवेश प्लस

UIN: 512L317V02 | Plan No: 749

- ✓ अपनी पसंद के साथ 4 फंड्स में से निवेशित पूंजी में वृद्धि के हितलाभ के साथ जीवन बीमा संरक्षण प्रोथ फंड | वैलेन्ड फंड | सिक्वोर्ड फंड | बॉण्ड फंड
- ✓ बीमा राशि का प्रकार तथा निवेश फंड चुनने की अनुकूलता
- ✓ गारण्टीड एडीशनल उपलब्ध
- ✓ पॉलिसी को 5 वर्ष के पश्चात बिना किसी स्थगन शुल्क के अनुरपित किया जा सकता है

एक नॉन-पार, लिक्विड, जीवन, व्यक्तिगत वचत योजना

हमारा बॉट्सपय नं. 8976862090

अधिक जानकारी के लिए आप अपने बीमा एजेंट/ नजदीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें या आपके शहर का नाम 56767474 पर एएएएएस करें

आयुर्विहित करों एलआईसी मोबाइल ऐप

विजिट करें: licindia.in

कॉल सेंटर सविन (022) 6827 6827

हमें फॉलो करें: f t i s in LIC India Forever IRDAI Regn No.: 512



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC1P/2024-25/41/Hin

नकली फोन कॉल और झूठे/घोषणापूर्वी पूर्ण ऑफर से सावधान रहें। आईआईसीआई जीवन बीमा पॉलिसियों की जांच, बीमन घोषित करने के निदेश जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं हैं। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे पुलिस में इसकी रिवायत दर्ज करवाएं। किसी सम्पान से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए किसी पुरतिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

लिखित इंधोरेन्स प्रोडक्ट्स परस्परिक इंधोरेन्स प्रोडक्ट्स से भिन्न होते हैं तथा उनके साथ जोखिम घटक होते हैं।

लिखित इंधोरेन्स पॉलिसियों में अदा किए गए प्रीमियम के साथ पूंजी बाजार तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंडेक्स से जुड़े निवेश जोखिम होते हैं। फंड की कार्यकुशलता तथा पूंजी बाजार/सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंडेक्स को प्रभावित करने वाले घटकों के आधार पर गुणवत्त के एन्वैरिमेंट घट-बढ़ सकते हैं तथा बीमित व्यक्ति अपने निवेशों के भिन्न रूप विमोदर होना। भारतीय जीवन बीमा निगम/लाइफ इंधोरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केवल जीवन बीमा कंपनी का नाम है तथा निवेश प्लस केवल लिखित इंधोरेन्स संविदा का नाम है तथा किसी भी रूप में संविदा की गुणवत्ता, इसकी भावी संपादनवा या आमदियों की और संकेत नहीं करता है। कृपया अपने बीमा एजेंट या मध्यवर्ती या इंधोरेन्स कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी दस्तावेज से संबंधित जोखिमों और लागू प्रमारों की जानकारी प्राप्त करें। इस संविदा के अंतर्गत पेश किए गए विभिन्न फंडस केवल फंडस के नाम हैं तथा वे किसी भी रूप में इन प्लान्स की गुणवत्ता, उनकी भावी संपादनवाओं तथा आमदियों की और संकेत नहीं करते हैं।

नकल पर नकेल, 146 पेपरों में जीरो पेपरलीक : बेढ़म

गृह और कारागार विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित

जयपुर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने हुए अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाया राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस जीरो टोलरेंस की नीति अपनाकर सख्त कार्रवाई कर रही है। जनता के सम्मान, जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करना हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य है।

बेढ़म सोमवार को विधान सभा में गृह विभाग की (मांग संख्या-18) एवं कारागार विभाग की (मांग संख्या-19) अनुदान मांगों पर हुई बैठक का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय 'क्रौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित' प्रजा के सुख में शासक का सुख निहित है, प्रजा के हित में उसे अपना हित दिखना चाहिए' के अनुरूप है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्ण संवेदनशीलता के साथ इस दिशा में अहम निर्णय ले रहे हैं। चर्चा के बाद सदन ने गृह विभाग की 116 अरब 57

करोड़ 7 लाख 84 हजार रूपए एवं कारागार विभाग की 3 अरब 68 करोड़ 47 लाख 11 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।

बेढ़म ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद अपराधियों में भय बढ़ा है। समझा अपराध की स्थिति में राज्य में वर्ष 2023 में जहां 2 लाख 31 हजार 240 प्रकरण दर्ज हुए थे। इसके बाद वर्ष 2024 में 2 लाख 13 हजार 351 प्रकरण ही दर्ज हुए ऐसे में 17 हजार 889 प्रकरणों की कमी आई है। यह 7.74 प्रतिशत की गिरावट है। ये आंकड़े हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की स्थिति को दर्शाते हैं।

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का आदर्श वाक्य 'यत्र नार्यस्तु पुष्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' है। यह नारी शक्ति के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को दर्शाता है। महिला संबंधित घटनाओं की रोकथाम और भयमुक्त वातावरण के लिए 250

कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन और 1 हजार कॉन्स्टेबल के पदों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। साथ ही, 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। मोबाइल एप 'महिला हेल्पलाइन नंबर 1090' जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से ही महिला अपराधों में कमी आई है।

बेढ़म ने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में 19 परीक्षा पेपरों में से 17 के पेपरलीक हुए थे। उन पर एसआईटी का गठन कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं से जीरो पेपरलीक का वादा किया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 1 जनवरी 2024 से आज तक 146 परीक्षाएं बिना पेपरलीक कराई गईं। अब एसआईटी द्वारा गत सरकार के दौरान हुई 43 परीक्षाओं की जांच की जा रही है, जिनमें 16 में पेपरलीक की घटनाएं सामने आई हैं और 27 में अन्य अनियमितताएं पाई गई हैं। एसआईटी

द्वारा अभी तक 331 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है। साथ ही, उपनिरीक्षक एवं प्लाटून परीक्षा-2021 में 91 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इनमें कार्रवाई करते हुए 36 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को बर्खास्त किया है।

गृह राज्य मंत्री ने बताया कि साइबर क्राइम पर ऑपरेशन एंटी वायरस तथा साइबर शिल्ड के तहत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। सरकार ने साइबर क्राइम के जरिए आमजन की गाड़ी कमाई के पैसे पर डाका डालने वालों पर अभियान चलाकर सख्ती कार्रवाई की है। इसमें 255 मामलों में प्रकरण दर्ज कर 543 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा गया है। वर्ष 2023 से 31 जनवरी 2025 तक साइबर अपराध की रोकथाम के लिए कुल 1 लाख 76 514 फर्जी मोबाइल नंबर एवं 1 लाख 35 हजार 372 मोबाइल आईएमईआई हैडसेट ब्लॉक कराए गए।

जब आसन पैरो पर हो तब सदस्य मूवमेंट नहीं करेंगे : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि जब आसन पैरो पर हो तब कोई भी सदस्य न तो बाहर से अन्दर आयेंगे और न ही अंदर से बाहर जायेंगे। जब आसन पैरो पर हो, तब सदन में सभी अपने सीटों पर बैठेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। विधायक, आसन के बोलेते वक्त अपनी सीटों से नहीं उठें और न ही कोई बाहर से सदन में प्रवेश करें।

सोमवार को विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने सदन में व्यवस्था देते हुये विधायक से कहा कि सदन में प्रत्येक विधायक की बात को सुना जायें। जब विधायक सदन में अपनी बात रख रहे हो तब उन्हें टीका भी नहीं जायें। देवनानी ने कहा कि सभी विधायक भाषा में शालीनता का पूरा ध्यान रखें। किसी विधायक द्वारा सदन को संबोधित करते समय अन्य विधायक उनके सामने से ना निकलें। देवनानी ने कहा कि सदन की यह बहुत पुरानी परंपरा है। सदन में फोन पर बात करना प्रतिबंधित है। नाम पुकारने पर ही संबोधित सदस्य बोले। देवनानी ने कहा कि अनुदान मांगो पर संबोधित मंत्री और संबोधित अधिकारी का सदन में मौजूद रहना आवश्यक है।

भजनलाल सरकार के नेतृत्व में रीट और आरएएस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न : डॉ.सतीश पूनिया

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने रीट पात्रता परीक्षा 2025 के सफल आयोजन को लेकर



भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ.सतीश पूनिया प्रेस से रूबरू हुए।

■ 'राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर गहलोट को दिया पाप का दंड'

भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉ पूनिया ने कहा कि रीट परीक्षा निर्बंधन रूप से आयोजित करवाने पर प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भाजपा सरकार ने प्रदेशभर में शांतिपूर्ण रूप से रीट परीक्षा कराई। जबकि पूर्ववर्ती गहलोट सरकार के कार्यकाल में रीट का पेपर आउट हुआ था और प्रदेश के 70 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था। गहलोट के कार्यकाल में रीट ही नहीं, पटवारी भर्ती, कॉस्टेबल भर्ती, जेईएन भर्ती, एसआई भर्ती, लाईब्रेरियन भर्ती, वनरक्षक सहित 19 परीक्षाओं के पेपरलीक हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि गहलोट के पाप का दंड राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके दिया।

पूनिया ने कहा कि कांग्रेस राज में प्रदेश में अराजकता का माहौल हो गया था। पेपरलीक की गुंज देशभर में पहुंची

और राजस्थान पेपरलीक के मामले में देशभर में बदनाम हुआ। इसके लिए गहलोट और कांग्रेस सरकार सीधे तौर पर दोषी थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ना केवल रीट परीक्षा का सफल आयोजन कराया, बल्कि आरएएस भर्ती परीक्षा भी शांतिपूर्ण संपन्न कराई। इतना ही नहीं, कांग्रेस राज में भर्ती परीक्षाओं के दौरान प्रदेश में घंटों नेटबंदी की जाती रही, जिससे आमजन परेशान हुआ और करोड़ों रूपए का व्यारार भी प्रभावित हुआ, लेकिन भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के दौरान नेटबंदी पर रोक लगाई। कश्मीर में आतंकवाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नेटबंदी करने पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा मुद्दा बनाया जाता था, लेकिन बाद में इन्हीं कांग्रेसियों ने

परीक्षाओं में नेटबंदी करना शुरू कर दिया था। भाजपा सरकार ने रीट और आरएएस भर्ती परीक्षा बिना नेटबंदी के शांतिपूर्ण संपन्न कराई। ऐसे में भाजपा सरकार का अभिनंदन।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेसी नेता अधिकांश तौर पर अपनी हार के लिए जिम्मेदार ईवीएम को बताते हैं, जबकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का सत्ता से बाहर जाने के 10 कारणों में से मुख्य कारण पेपरलीक रहा है। पेपरलीक को लेकर सदन में और सदन के बाहर भी व्यापक आंदोलन हुए, कांग्रेस सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता था, कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस का दमनकरण भी चलाया, लाठी के दम पर आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया।

छात्राओं ने विधानसभा को देखा



राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से सोमवार को यहाँ राजस्थान विधान सभा में कानोडिया पी.जी महिला महाविद्यालय की राजनीति विज्ञान विषय की स्नातकोत्तर की छात्राओं ने मुलाकात की। महाविद्यालय की छात्राओं ने सोमवार को राजस्थान विधान सभा के सदन में प्रथमकाल की प्रक्रिया को देखा और सदन में विधायकों की चर्चा को सुना। महाविद्यालय की प्राध्यापक डॉ. निमिषा गंड, संजू शर्मा और स्वाती ने छात्राओं के दल के साथ विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय को भी देखा।

अजय सिंह किलक ने नागौर एसपी पर आरोप लगाये

जयपुर। डेगना विधायक और पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक ने गृह विभाग की अनुदान मांगों पर नागौर एसपी और इलाके की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। किलक ने कहा कि मैं सदन में आरोप लगा रहा हूँ कि नागौर एसपी भरे से व्यक्तिगत दुर्भावना रखते हैं, भरे कई कार्यकर्ताओं से भी दुर्भावना रखते हैं। थानवा क्षेत्र के लोगों ने मुझे बताया कि वहां पर थानेदार पैसा लेकर अवैध बजरी निकलवाता है। हर टुक से पांच हजार और टैक्टर-ट्रॉली से भी मोटी रकम वसूलता है। इस संबंध में मैंने व्यक्तिगत रूप से नागौर एसपी को जानकारी दी कि वहां थानेदार पैसे लेकर अवैध बजरी खनन करता है। मैंने एसपी से बात की तो उनका जवाब था मैं खुद रिश्त नही लेता, तो मैंने कहा मैं भी रिश्त नही लेता हूँ मैं भी वहां का विधायक हूँ। किलक ने कहा कि थानवा के थानेदार की मुख्यमंत्री से शिकायत की, तब जाकर उसे हटाया

■ कहा, "नागौर एसपी भरे से व्यक्तिगत दुर्भावना रखते हैं, भरे कई कार्यकर्ताओं से भी दुर्भावना रखते हैं।"

जबकि नागौर एसपी ने उस थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सहायक वनपाल ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो उस थानेदार ने उससे ही बदतमीजी की। शान्ति धारीवाल ने बहस के दौरान मंत्री किरौड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों पर तंज कसा। धारीवाल ने कहा कि टेलीग्राफ एक्ट की क्या हालत की है आपने। एक मंत्री कह रहा है मेरा फोन टैप हो रहा है, दूसरा मंत्री कह रहा है नहीं हो रहा। दूसरी बार मंत्री ने फिर कहा कि अब भी हो रहा है, क्या तमाशा है?

ऑपरेशन क्लीन स्वीप : पुलिस ने नशे के सौदागर पर कसा शिकंजा

जयपुर। सिंधी कैप थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 400 ग्राम डोडा चूरा पाउडर और 125 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को धर दबोचा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अभित कुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेंट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सिंधी कैप थाना पुलिस ने किशोर सिंह शेखावत निवासी सरदारशहर, जिला चूरू गिरफ्तार किया है।

रेलवे कर्मचारी कर रहा था पाकिस्तान के लिए जासूसी, गिरफ्तार

■ रेलवे कर्मचारी लड़की से था संपर्क में, पुलिस जुटा रही आरोपी के बैंक खाते और फोन कॉल की डिटेल्स

था। जांच के दौरान इंटरलिंगेज की टीम को कई साक्ष्य आरोपी भवानी सिंह के खिलाफ मिलने पर उसे गिरफ्तार किया गया।

इंटरलिंगेज के अधिकारियों ने बताया कि बीकानेर जिले के सामरिक महत्व से आज संवेदनशील महाजन रेलवे स्टेशन क्षेत्र की निगरानी के दौरान टीम ने यहाँ पदस्थापित पॉइंटमैन भवानी सिंह को गिरफ्तार किया। भवानी सिंह

की गतिविधियाँ संदिग्ध होने पर उस पर टीम ने निगरानी रखना शुरू किया। पुष्टि होने पर दो दिन पहले भवानी को डिटेन कर जयपुर लाया गया जहाँ पर पूछताछ में कई जानकारी सामने आई। पूछताछ के बाद सोमवार को उसे गिरफ्तार किया गया।

महाजन फोल्ड फायरिंग रेंज भारतीय सेना का अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में

सैन्यकर्मियों एवं सेना के सभी प्रकार के सामान का आवागमन महाजन रेलवे स्टेशन के माध्यम से ही होता है। भवानी सिंह ने युवती के फेर में फंस कर हनीट्रैप का शिकार हुआ साथ ही उस ने धन के लोभ में आकर सोशल मीडिया के माध्यम से पाक महिला एजेंट के संपर्क में रह कर महाजन रेलवे स्टेशन पर सेना की होने वाली सभी गतिविधियों की संवेदनशील एवं गोपनीय सूचना निरंतर देता रहा। इन सभी प्रकार की जानकारी देने की एवज में भवानी सिंह ने आईएसआई से पैसा ले रहा था।

देवनानी ने शिक्षाविद् अशोक गुप्ता के निधन पर जताया शोक

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिक्षाविद् अशोक गुप्ता के निधन पर गहरा दुःख जताया है। देवनानी ने कहा कि स्व. गुप्ता ने महिला शिक्षा को नये आयाम दिये। शिक्षा में दिग्दे गये स्व. गुप्ता के योगदान को प्रदेश में सदैव याद रखा जाएगा। देवनानी ने कहा कि स्व. गुप्ता ने निजी क्षेत्र में शिक्षा को विस्तार देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। देवनानी ने कहा कि स्व. अशोक गुप्ता सिर्फ एक शिक्षाविद् ही नहीं थे, वे शिक्षा के प्रबुद्ध विचारक थे। उन्होंने आई.एस.ईएस विश्वविद्यालय और स्कूल की स्थापना कर शिक्षा को किताबी ज्ञान से आगे ले जाकर व्यावहारिकता, अनुशासन और नवाचार का संगम बनाया।

दवाइयों के दुरुपयोग पर सख्त कदम उठाएगी सरकार : खींवसर

जयपुर (विस्.)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में दवाइयों और ड्रग्स के दुरुपयोग की जांच कर सख्त कदम उठाएगी।

खींवसर ने शून्यकाल में विधायक गुरवीर सिंह के ध्यानकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कई क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उपचार के लिए उपलब्ध आवश्यक दवाइयों और ड्रग्स का दुरुपयोग कई युवाओं द्वारा नशे के लिए हो रहा है। इस क्षेत्र में बिकने वाले नौ ड्रग्स को सरकार ने बैन भी किया हुआ है। उन्होंने कहा कि

रैपिड एक्शन फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च

जयपुर। जयपुर में रमजान माह व आगामी त्योहारों को देखते हुए किसी अग्रिय घटनाओं से निवृत्तने के लिए पुलिस थाना रामगंज इलाका थाना क्षेत्र में केंद्रीय पुलिस बल सीआरपीएफ की यूनिट रैपिड एक्शन फोर्स की सी 83 टाटालियन की कम्पनी के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर उतर राशि डोगरा डूडी ने बताया कि रमजान माह व आगामी त्योहारों के मध्यनजर केंद्रीय पुलिस बल सीआरपीएफ की यूनिट रैपिड एक्शन फोर्स की सी 83 टाटालियन की कम्पनी के साथ सोमवार को पुलिस थाना रामगंज, गलता गेट, सुभाष चौक में संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में परिचित अभ्यास किया।

सागर-सामाचार रविकाश ने अमृतसर में शुरु की दो नई शाखाएं



जयपुर। रविकाश फाइनेंशियल ने अपने विस्तार अभियान के तहत 3 मार्च को पंजाब के अमृतसर में अपना 26वाँ और 27वीं शाखा एक साथ खोली। एक शाखा रणजीत एवेन्यू में और दूसरी मैन बाजार, नवी सड़क में शुरु की है। यह कदम कंपनी की पंजाब में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। रविकाश फाइनेंशियल के निदेशक विकास ओझा और रवि डीगर् ने नवीन शाखाओं का शुभारम्भ करते हुए कहा, "हमारी कंपनी की नींव ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिकता पर आधारित है।" उन्होंने आगे कहा कि कंपनी के दो मुख्य लक्ष्य हैं: कंपनी के साथ जुड़े ऋण वितरण को समय पर पैसा देना और पूरा पैसा देना। ओझा और डीगर् ने कहा, "हमारा लक्ष्य धीरे-धीरे पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करना है।" कंपनी का मिशन अपने ग्राहकों को विश्वसनीय और पारदर्शी सेवाएँ प्रदान करना है।

डॉ. कमलेश शर्मा सम्मानित

जयपुर। बाघ संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत रणधर्मीर की विश्व प्रसिद्ध संस्थाटाइगर वॉच की ओर से वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले प्रतिष्ठित श्री फ्लोहर्सिंग राटोड स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कारों के तहत पर्यावरणीय विषयों पर लेखन और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के माध्यम से पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में जनजागरूकता पैदा करने के लिए पुलिस मुख्यालय में कार्यरत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर व लेखक डॉ. कमलेश शर्मा को पीएल एंड नेचर' सर्विसेज टू वाइल्डलाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

आईआईएस गुप के संस्थापक डॉ अशोक गुप्ता का निधन

जयपुर। आईआईएस गुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के संस्थापक और आईआईएस यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ अशोक गुप्ता का असामयिक निधन आज सुबह हो गया है। उनके निधन से राजस्थान के शैक्षणिक जगत में गहरा शोक है। स्कूल शिक्षक के तौर पर अपनी शिक्षण यात्रा शुरू कर श्रेष्ठ संस्थाओं की स्थापना करने वाले डॉ गुप्ता 77 वर्ष के थे। उनके द्वारा स्थापित आईआईएस स्कूल, प्ले हाउस, आईसीजी-आईआईएस डीप्ट यूनिवर्सिटी और आईएसआईएम संस्थान, देश भर में गुणवत्ता के लिए पहचाने जाते हैं। आईआईएस शैक्षणिक गुप के एजीक्यूटिव सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी राजीव सोगानी ने बताया कि श्रद्धांजलि स्वरूप, इन शैक्षणिक संस्थाओं में दो दिन 4 और 5 मार्च को शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेंगे।

प्रो. प्रमोद येवले कुलपति नियुक्त

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागडे ने आदेश जारी कर प्रो. (डॉ.) प्रमोद येवले को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति पद पर नियुक्त किया है। श्री बागडे ने चयन समिति की सिफारिश पर एवं राज्य सरकार के परामर्श से यह आदेश जारी किया है। बागडे ने कुलपति पद पर यह नियुक्ति प्रो. प्रमोद येवले के कार्यभार संचालने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले के लिए की है।

सिटीज 2.0 में जयपुर और उदयपुर का चयन

जयपुर। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सिटी इन्वेस्टमेंट टू इकोवेट इंटिग्रेटेड पंड स्ट्रैटेजि चैलेंज (सिटीज 2.0) कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 स्मार्ट सिटीज में से जयपुर तथा उदयपुर सहित 18 शहरों का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत जयपुर तथा उदयपुर शहर में एकूकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु परियोजना स्वीकृत की गई है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि का 80 फीसदी अनुदान एएफ डी, कैपेफंडस्वरूप, एंड ई यू के माध्यम से ऋण स्वरूप उपलब्ध

कराया जाएगा। अनुदान का 50 फीसदी केंद्र सरकार तथा 50 फीसदी राज्य सरकार द्वारा ब्याज सहित चुकाया जाना है। परियोजना की शेष लागत 20 फीसदी राशि राज्य सरकार अथवा युएलबी अथवा स्मार्ट सिटी द्वारा वहन की जाएगी। जयपुर स्मार्ट सिटी तथा उदयपुर स्मार्ट सिटी द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर को और अधिक साफ सुथरा बनाने हेतु पर्यावरण उन्मुख अपशिष्ट प्रबंधन कार्य पर ध्यान देते हुए संकुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा।

आईआईटी बाबा को जयपुर पुलिस ने होटल से पकड़ा

जयपुर। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह को जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। शिप्रापथ थाना पुलिस ने एक होटल से बाबा को हिरासत में लिया और फिर बाद में जमानत मुचलके पर छोड़ भी दिया गया। बाबा के पास गांजा भी बरामद किया गया है। बाबा पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस को तलाशी में बाबा के पास दो ग्राम गांजा

दिगंत आनंद ने बताया कि पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि रिद्धि सिद्धि पाक क्लासिक होटल में अभय सिंह नाम का युवक सुसाइड का प्रयास कर रहा है। जिसके चलते पुलिस होटल पहुंची। यहां आईआईटी बाबा अभय सिंह मिला। सिंह ने पुलिस को बताया कि वह गांजे के नशे में था। इस दौरान उसने नशे में कोई सूचना दी हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस को तलाशी में बाबा के पास दो ग्राम गांजा

भी बरामद किया गया। पुलिस ने थाने में लाकर सिंह को जमानत मुचलके पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने बताया कि बाबा के पास दो ग्राम गांजा ही बरामद हुआ था। थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने बताया कि अभय सिंह के कब्जे से मिला गांजा की मात्रा कम होने के कारण जमानत पर रिहा कर दिया। अभय सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

बिजयनगर ब्लैकमेल कांड : आरोपियों के साथ पेशी के दौरान वकीलों ने मारपीट की

मामले में अभी तक पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार व तीन नाबालिगों को निरुद्ध किया है

अजमेर, (कासं)। ब्यावर जिले के बिजयनगर में नाबालिग छात्राओं से रैप व ब्लैकमेल कांड के मुखिया पूर्व पार्षद हाकिम कुरेशी को सोमवार को लंबे समय के रिमांड के बाद अजमेर की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान अजमेर कोर्ट में वकीलों ने कुरेशी की पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करते हुए कुरेशी को कोर्ट से पुलिस वेन में लेकर रवाना हुई। इससे पहले भी इस मामले में अजमेर के वकीलों ने

पिटाई की थी। सरकारी वकील रूपेंद्र सिंह परिहार ने सोमवार को रिमांड के बाद हाकिम कुरेशी को अदालत में पेश किया था। कुरेशी को कोर्ट ने 11 मार्च तक जेल भेज दिया। इस मामले में अभी तक पुलिस ने 10 आरोपियों गिरफ्तार व तीन नाबालिगों को निरुद्ध किया है।

ब्यावर जिले के बिजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में पुलिस ने सोमवार को पूर्व पार्षद हाकिम कुरेशी रिमांड अवधि समाप्त होने पर अजमेर

- सोमवार को अजमेर जिले का श्रीनगर कस्बा पूरी तरह बंद रहा, व्यापारियों ने समर्थन दिया**

की पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि आरोपियों का सहयोग करने वाले पूर्व पार्षद हाकिम कुरेशी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने

दो बार उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था, सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। जहां उन्हें 11 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए।

गौरतलब है कि प्रकरण में अन्य आरोपी सोहेल, रेहान, श्रवण जाट, करीम, आशिक, लुकमान, अफराज, पूर्व पार्षद हाकिम कुरेशी, जावेद, कैंफे संचालक सांवरमल न्यायिक अभिरक्षा में हैं, साथ ही मामले में 3 नाबालिगों

को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। वहीं ब्लैकमेल कांड को लेकर सकल हिंदू समाज में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को अजमेर जिले का श्रीनगर कस्बा पूरी तरह बंद रहा, व्यापारियों ने दुकानें बंद का समर्थन करते हुए प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद के दौरान स्कूल, मेडिकल शॉप, बस सहित अन्य सेवा बहाल रही। ग्रामीणों ने रैली निकाल कर आरोपियों को फांसी दिए जाने और सीबीआई जांच की मांग की।

तोड़फोड़ और फायरिंग करने के मामले में रिपोर्ट मांगी

श्रीगंगानगर, (निर्सं)। महिाँवाली में 1 फरवरी को इन्द्राज खान के घर पर जानलेवा हमले, तोड़फोड़ और फायरिंग के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने नोटिस में पुलिस अधीक्षक से 4 सप्ताह के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है।

पीड़ित ने बताया कि उक्त घटना के बाद चुनावट पुलिस लगातार केस को झूठा साबित करने और मामले को रफा-दफा करने में लगी है। मैंने वह विषय पुलिस महानिदेशक और आईजी बीकानेर को भी अवगत कराया है। घटना के बाद से पूरा परिवार पुलिस निष्क्रियता के चलते भयभीत है। हमने पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से भी सुरक्षा की मांग की है और उससे मिलकर भी आये हैं। मामले में रजत, प्रिंस, युवराज, सबीर उर्फ मोनू, सीमा देवी और अमन पत्नी अमन सोनी मुख्य आरोपी है।

पीड़ित ने बताया कि पुलिस सभी तक मामले में दो महिला अभियुक्तों सीमा देवी और अमन पत्नी अमन सोनी को नहीं पकड़ रही है जो कि पूरी घटना के मास्टरमाइंड है। सभी अभियुक्तों को राजनितिक संरक्षण प्राप्त है। अमन सोनी और सीमा देवी को अभी तक पुलिस ने पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है। पीड़ित इन्द्राज खान ने 18 फरवरी को आयोग के सदस्य प्रियांक कानूगरो को पत्र लिखकर पुलिस की निष्क्रियता और अपराधियों को दिए जा रहे संरक्षण का

मामला अवगत करवाया था जिस पर आयोग ने केस दर्ज कर श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक को चार सप्ताह में करवाई रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देश दिया है। यहां तक कि पुलिस एफआईआर में अभियुक्त अमन पत्नी अमन सोनी का नाम है, लेकिन उसने अपनी राजनीतिक पहुँच के चलते अपनी जगह अपने पति को जेल भिजवा दिया जबकि घटना में वह खुद शामिल थी। दोनों को नाम एक जैसा होने का फायदा उठाकर, चुनावट पुलिस अमन के साथ मिलकर उसका नाम हटाने में है, जबकि वह और सीमा देवी घटना की मास्टरमाइंड है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। अपराधियों ने यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया पर चुनावट पुलिस के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, और धमकी भर गानों का इस्तेमाल कर रहे है। पीड़ित के अनुसार मैंने यह अभियुक्तों के रीलेस और सोशल मीडिया पोस्ट्स आईजी को भी भिजवाए थे और पुलिस द्वारा उनको संरक्षण दिए जाने का मामला उनके समक्ष रखा था।

मामला मीडिया में आने के बाद और पुलिस महानिदेशक को शिकायत के बाद पुलिस ने 18 फरवरी को अभियुक्त रजत उर्फ डॉलर और अमन सोनी (अभियुक्त अमन का पति) को गिरफ्तार कर जेल भेजा लेकिन पुलिस ने मिली-भगत से एक जैसा नाम होने का फायदा उठाकर अमन सोनी को अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया जिनको कोर्ट द्वारा 24 फरवरी को जमानत दे दी गई।

हमले में एक घायल

भीलवाड़ा, (निर्सं)। जिले के हमीरगढ क्षेत्र में संगम इंडिया लिमिटेड, डेनिम के मैनेजर संजय व्यास पर सोमवार सुबह बीएसएल गेट के पास एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने कातिलाना हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यास को उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

जानकारी के अनुसार संजय व्यास संगम इंडिया लिमिटेड, डेनिम यूनिट, बीलियाकलां में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। व्यास सोमवार सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार को बीएसएल गेट के नजदीक देवनारायण मंदिर के सामने ब्रेकर पर बाबू गुर्जर, बृजेश गुर्जर, गोपाल गुर्जर व कमलेश गुर्जर सहित 1०-15 लोगों ने रोक और गाली-गलौच करते हुए लोहे के पाइप व सरियों से व्यास पर कातिलाना वृत्त चलावा कर दिया। हमले में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं और वे लहलुहान हो गये।

चाकूबाजी के मामले में तीन गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निर्सं)। शहर की प्रताप नगर थाना पुलिस ने गत दिनों पीपन्टी चौपट पर हुई चाकूबाजी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सूरजोत्त सिंह ने बताया कि शाहपुरा हाल पटेल नगर निवासी चांद खां पुत्र शौकत खान कायमखानी ने 25 जनवरी को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 जनवरी को उसका बेटा इरशाद, बाबू उर्फ विश्वजीत, लोकेश, अक्षत, भरत एसटेक स्कूल के पास बैठकर कार्यालय संबंधित मीटिंग कर रहे थे। बातो ही बातों में लोकेश बलाई व बाबू के बीच विवाद हो गया। दोनों ही पक्ष वहां से रवाना होकर रात 11:3० बजे आपस में इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन मामलों को लेकर आरोपियों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई। लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। जिनके पक्ष का हमें इंतजाम रहेगा।

केडिया ने बताया कि उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ऐसे सारे सबूत वें जांच में शामिल करवाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आरोपियों के अपराधिक रिकार्ड और पुलिस द्वारा समय-समय पर की गई आरोपियों के विरुद्ध टिप्पणों को भी उपलब्ध करवाएंगे।

वन अधिकारी की हत्या पर श्रीगंगानगर में आक्रोश फैला

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और परिजनों को मुआवजा देने की मांग

श्रीगंगानगर, (निर्सं)। जिले में राजस्थान वन अधीनस्थ कर्मचारि संघ और रेंजर एसोसिएशन ने स्थानीय प्रशासन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 24 फरवरी को राजसमंद जिले में खनन माफिया के द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी किशोर कुमार की हत्या करने के मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही मृतक क्षेत्रीय वन अधिकारी किशोर कुमार को शहीद का दर्जा देने के साथ ही परिजनों को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग की गई है।

राजौव बिशोई ने बताया कि 24 फरवरी को राजसमंद जिले के बिजा गुडुा में वन भूमि पर अवैध खनन को रोकने के दौरान खनन माफिया द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी किशोर कुमार और वन रक्षक विष्णु कुमार पर ट्रैक्टर से हमला किया

गया। इस हमले में किशोर कुमार की मौत हो गई, जबकि विष्णु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रेम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि यह घटना वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर अतिक्रमण के मामलों में बढ़ती घटनाओं के बावजूद वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन और स्टाफ की कमी है, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में है। इस सिलसिले में राज्य सरकार से मांग की गई है कि इस मामले में तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक किशोर कुमार को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाए। इसके अलावा घायल वन रक्षक विष्णु कुमार को उनके साहसिक कार्य के लिए गैलेंट्री पदोत्रति दी जाए और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही राज्य के

प्रत्येक वन रेंज में पर्याप्त वाहन और स्टाफ की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से निपटा जा सके।

सीएम के नाम दिए गए ज्ञापन के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के बावजूद आवश्यक हथियारों की अनुपलब्धता और सीमित स्टाफ की स्थिति में कार्य करना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा पर लगातार खतरा मंडराता है। इस मामले में राज्य सरकार से अपील की गई है कि क्षेत्रीय वन अधिकारियों को केंद्र सरकार के मानकों और अन्य राज्यों की तरह सभी आवश्यक सुविधाएं और शक्तियां प्रदान की जाएं, ताकि अवैध खनन और अतिक्रमण में एवं अभिहित अधिकारी को जाा सके। सभी कर्मियों ने राज्य सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की है।

बरामद किए कंकाल की पहचान हुई

पिता ने कपड़ों के टुकड़ों के आधार पर पहचान की थी

श्रीगंगानगर, (निर्सं)। चुनावढ़ पुलिस द्वारा 24 एमएल रोही से बरामद किए गए कंकाल की दो मार्च को पहचान हो गई है। यह अबोहर की ऋषि कॉलोनी की गली नंबर एक निवासी 26 वर्षीय अनिल अरोड़ा पुत्री हरिकिशन अरोड़ा का शव था। वंदना के पिता ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में अपनी बेटी के शव-विशत कंकाल के शेष बचे पहने कपड़ों के टुकड़ों के आधार पर पहचान की थी।

जानकारी के अनुसार वंदना 22 फरवरी से लापता थी। उसने अपनी ढाई साल की बेटी को साथ लेकर बीकानेर कैनाल में छलांग लगाकर आत्महत्या की थी। वंदना के पिता की ओर से 26 फरवरी को अबोहर सिटी वन थाने में गुमशुदगी दर्ज करावाई थी। इसके साथ ही पंजाब और गंगनहर के आसपास के थानों को सूचनाई-मेल से भिजवाई गई थी ताकि इसकी पहचान हो सके।

पिता हरिकिशन अरोड़ा तथा अबोहर सिटी वन के एएसआई भूपेंद्रसिंह जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने हमारे सामने वंदना के शव की शिनाखा की। इसके बाद एएसआई भूपेंद्रसिंह ने शव की सुपुर्दी के लिए चुनावढ़ पुलिस के नाम पत्र लिखकर शव अपने कब्जे ले लिया और एंबुलेंस की मदद से अबोहर के सरकारी अस्पताल ले गए। वहां पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है। वंदना के पिता की ओर से अब उसके पति पर आत्महत्या दुष्प्रेरण का मुकदमा दर्ज करवाया है। चुनावढ़ पुलिस ने यह शव-विशत शव पानी में बहकर आएं को 24 एमएल की रोही में नहर के अंदर से किसान की सूचना पर बरामद किया था। इसकी पहचान को खबरें प्रकाशित कराईं थी। इसके साथ ही पंजाब और गंगनहर के आसपास के थानों को सूचनाई-मेल से भिजवाई गई थी ताकि इसकी पहचान हो सके।

फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में आईएएस अधिकारी को कोर्ट ने तलब किया

ब्यावर, (निर्सं)। आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित किये जाने के मामले में फर्जी दस्तावेज बनाकर उस पर फर्जी हस्ताक्षर के एक मामले में ब्यावर कोर्ट ने आईएएस अधिकारी मुद्दुल सिंह व अन्य को तलब किया है।

तेजा चौक तम्बाकू गली ब्यावर निवासी कन्हैयालाल साहू के एक मामले में उसके पड़ोसी रमेश कुमार सोनी द्वारा नगर परिषद ब्यावर से आवासीय जायदाद की निर्माण स्वीकृति लेकर उसमें वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित कर ली थी, जिसे लेकर कन्हैयालाल साहू ने सूचना के अधिकार कानून 2००5 के तहत नगर परिषद ब्यावर ने उक्त निर्माण के संबंध में जानकारीयां चाही थी जिस पर सूचना नहीं मिलने पर कन्हैयालाल साहू को

राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर में द्वितीय अपील करनी पड़ी, जिस पर आयोग द्वारा नगर परिषद ब्यावर को आदेश देते हुए 15 दिवस में नि:शुल्क सूचना देने के आदेश दिये थे। तत्समय तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त आईएएस मुद्दुल सिंह थे जो कि लोक सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अवैध निर्माणकर्ता रमेश कुमार सोनी व अन्य के साथ मिलीभगत कर राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर के आदेश पर सूचना देने से बचने के उद्देश्य से नगर परिषद ब्यावर में ही कन्हैयालाल साहू के नाम से न केवल जाली व कूटरचित संतुष्टि पत्र बना डाला, बल्कि उक्त कूटरचित दस्तावेज पर कन्हैयालाल साहू के फर्जी हस्ताक्षर तक कर दिये व उक्त कूटरचित संतुष्टि

पत्र को असली बताते हुए राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर को भिजवा दिया।

उक्त फर्जीकारिता व कूटरचना की जानकारी होते ही कन्हैयालाल साहू ने तुरन्त इसकी जानकारी तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त आईएएस मुद्दुल सिंह को व्यक्तिगत उपस्थित होकर लिखित में दी लेकिन मुद्दुल सिंह ने कोई कार्यवाही नहीं की जिस पर परिव्रादी ने जिला कलेक्टर ब्यावर व निदेशक स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को भी लिखित शिकायत दी, लेकिन उन्होंने भी अपने अधिकारियों को व अन्य दोषीयों को बचाने के उद्देश्य से जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं की। जिस पर मजबूर होकर पीड़ित कन्हैयालाल साहू ने अपने अधिवक्ता नीलेश बुइड़ के मार्फत

दो पत्रकारों ने एक व्यक्ति से ब्लैकमेल कर एक लाख मांगे

झुंझुनू, (निर्सं)। जिला मुख्यालय के दो पत्रकारों ने एक व्यक्ति से एक लाख रूपए की अनुचित मांग की। पैसे नहीं देने और उनकी बात नहीं मानने पर इस व्यक्ति के खिलाफ गलत तथ्यों के साथ खबरें प्रकाशित कर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अब इस मामले में पीड़ित ने थाने में पत्रकारों और उनके साथ षडयंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित भी पेशे से पत्रकार है।

पुलिस में दर्ज करवाई एफआईआर के अनुसार जिला मुख्यालय पर कार्यरत पत्रकार संदीप केडिया ने झुंझुनू के पत्रकार पिताम्बर शर्मा, प्रदीप गढ़वाल, सुरेश सैनी, चूरू के पत्रकार राधेश्याम चोटिया, दो समाचार पत्रों के संपादक तथा उनके चूरू व झुंझुनू सम्प्रि प्रभावी के अलावा बाल कल्याण सहित झुंझुनू की पूर्व अध्यक्ष अर्चना चौधरी, उनके पति कर्नल दिनेश कुमार तथा एक एजीओ संचालक बनवारीलाल सैनी व एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसमें परिव्रादी संदीप केडिया ने आरोप लगाया कि पिताम्बर शर्मा, प्रदीप

- मामले में पीड़ित ने थाने में कोतवाली में मामला दर्ज कराया है**

गढ़वाल, बनवारीलाल सैनी तथा राधेश्याम चोटिया चूरू ने उसके एक लाख रूपए और बाल कल्याण समिति की पूर्व अध्यक्ष अर्चना चौधरी तथा उसके पति कर्नल दिनेश कुमार से माफ़ी मांगने की बात कही। जब संदीप केडिया ने आरोपियों की बात नहीं मानी तो उन्होंने चूरू में दर्ज एक पॉक्सो मामले की पुरानी खबर को गलत तथ्यों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसमें उन्होंने कोर्ट के सही तथ्यों से परे गलत तथ्यों को सोशल मीडिया व समाचार पत्रों में प्रसारित किया। इसके अलावा एक पॉक्सो पीड़िता की पहचान को भी उजागर कर पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया। आरोपियों ने षडयंत्र रचकर संदीप केडिया के खिलाफ पूर्व में दी गई धमकी के अनुसार चूरू में एक झूठा पॉक्सो का मामला भी दर्ज करवाया। इस मामले की रिपोर्ट कोतवाली में अक्टूबर 2०24 में दी गई

वाल्मीकी समाज की बारात का सर्व हिन्दू समाज ने स्वागत किया

करोली, (नि.सं.) सवाई माधोपुर के गम्भीरा भाडीती से बाबूलाल वाल्मिकी के पुत्र विष्णु की बारात करोली जिले के सपोटरा तहसील के गाँव रानीपुरा जाखौदा में कालू हरिजन की बेटी शिवानी की बारात का सर्वसमाज के लोगो ने रानीपुरा में स्वागत किया, जिसमें सभी बारातियों को तिलक

- सभी बारातियों को तिलक लगाकर व पुष्पमाला पहनाकर स्वागत एवं अल्पाहार करवाया**

लगाकर व पुष्पमाला पहनाकर स्वागत एवं अल्पाहार करवाया गया। बारात में आये प्रत्येक बाराती को श्रीफल भेंट किया गया। श्रीफल को हिन्दू संस्कृति के अनुसार अशुकर के पत्ते, आम के पत्ते एवं कलावा से बाँधकर संस्कृति का परिचय दिया गया।
भारत के स्वागत में लगभग 15 समाजों के 1०0 से अधिक लोगों ने भाग लिया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। कार्यक्रम में दूसरे गाँवों से भी काफी मात्रा में स्वागत करने हेतु समाज सेवक पहुंचे। इसके बाद ग्राम के

सर्वोच्च अधिकारी का स्वागत किया।

पंच पटेलों एवं सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने मिलकर दूध के बग्गी (रथ) पर बिठारकर धूमधाम में वन्देमातरम्, जय श्री राम के नारों के साथ निकासी निकाली। बारात में आये वाल्मीकी समाज के 75 वर्षीय बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा सम्मान पाकर हमारा

जीवन धन्य हो गया है। समस्त ग्रामीणों को ऐसा दृश्य देखकर प्रसन्नता हुई। कार्यक्रम में कृष्णवल्लभ शर्मा,पवन कुमारा पुता, बाबूलाल सेवामिच्रतरेवले, पप्पू लाल मीना, मुनेश चंद मीना, चिंरंजी पटेल, रामभरोसी डीनर, जनमेद पटेल, शिवकुमार गुप्ता, रामधन

डाबिर, अमृतलाल जाखौदा, लक्ष्मी पटेल, श्याम सुंदर इनायती, बजरंगलाल पटेल, रामनिवास मीना, मनकेश, सुद्वजानी, मुकेश, बाबूलाल सैनी, राजेन्द्र मीणा, मदनमोहन कांबटी, भरतलाल रानीपुरा एवं ग्रामवासियों का सहयोग रहा।



कांग्रेस महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पाली में एनएसयूआई की "नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो" यात्रा में भाग लिया। उन्होंने रैली में साइकिल चलाकर युवाओं को नशा छोड़ने का संदेश दिया।

पायलट ने साइकिल चलाकर "नशा छोड़ो जीवन जोड़ो" यात्रा में भाग लिया

एनएसयूआई की साइकिल यात्रा जैसलमेर से जोधपुर, रोहट होते हुए पाली पहुँची

पाली, 3 मार्च, (निस)। कांग्रेस महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार को पाली में एनएसयूआई की "नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो" यात्रा का साइकिल चलाकर भाग लिया। यहां से यह साइकिल यात्रा सोजत तक जाएगी। पायलट पाली पहुंचे तो गांधी मूर्ति स्थित कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एनएसयूआई की नशा छोड़ो जीवन जोड़ो साइकिल यात्रा जैसलमेर से शुरू होकर जोधपुर रोहट होते हुए पाली पहुँची थी।

पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने कहा कि एनएसयूआई की ओर से यह जो नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो साइकिल यात्रा जैसलमेर से जयपुर तक निकाली जा रही है, यह कोई चुनावी यात्रा नहीं है और न ही वोदो मांगने के लिए निकाली जा रही है। कांग्रेस और एनएसयूआई अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए एनएसयूआई की ओर से यह रैली निकाल रही है, जिससे युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। इस रैली के जरिए अभी तक करीब 15 हजार युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई

■ सचिन पायलट ने कहा कि इस रैली के जरिए अब तक 15 हजार युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई जा चुकी है।

■ उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार का अभी तक सवा साल का कार्यकाल मेरी नजर में निराशाजनक है।

जा चुकी है। कार्यक्रम को जोधपुर के सांसद उम्मीदवार रहे करण सिंह ऊंचीवारिडा, रतन देवसारी, संगीता बेनीवाल, विधायक भीमराज भाटी, जिला अध्यक्ष अजीज दर्द ने भी संबोधित किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि मुझे अब तक सभी जगह सहयोग मिला है, पाली में युवाओं का अपार जनसमर्थन देखकर मुझे खुशी हुई है। कार्यक्रम में नसीम बाबो, कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष प्रवीण कोठारी, प्रदीप हिंङ्गड़, विधायक भीमराज भाटी, पूर्व विधायक खुशवीर सिंह, पूर्व प्रधान शोभा सोलंकी, नीलम बिरला, हकीम भाई महबूब टो, गणपत पटेल, यशपाल सिंह कृपावत, मांगू सिंह दुघवत, अमीन सहित कई कांग्रेस

नेता मौजूद थे। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की सरकार का अभी तक का सवा साल कार्यकाल मेरी नजर में निराशाजनक है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी काम नहीं होने से छाती पीट रहे हैं। प्रशासन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। किरोड़ोवाल मीणा मंत्री हैं या नहीं, यह पता ही नहीं चल रहा है। वे इस्तोफा देना चाहते हैं, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। उनके विभाग में काम नहीं हो रहा है। यह प्रश्न पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है। विधानसभा में जनता के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठा रहे हैं। भाजपा सरकार के मंत्री द ग से जवाब तक नहीं दे पा रहे।

रिपोर्टर्स क्लैक्टिव....

(प्रथम पृष्ठ का शेष) प्लेटफॉर्म को इन्कम टैक्स विभाग ने पहले चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी थी, हो सकता है कि उस ट्रस्ट को पिछले समय से टैक्स अदा करना पड़े।

डिजिटल ने कहा, "ऐसे समय जब भारत का प्रैस-स्वतंत्रता सूचकांक अब तक के सबसे नीचे स्तर पर पहुँच गया है तथा मुख्यधारा के मीडिया को लम्बी कतारों सरकार की चिरयलोटर्स बन गई हैं, केवल स्वतंत्र मीडिया प्रतिष्ठान ही वर्तमान सरकार और उसकी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।" बयान में आगे कहा गया, "इन्में से अधिकांश प्रतिष्ठान, जो सरकारी तथा व्यावसायिक (152) तथा श्रीलंका (150) से विज्ञापनों के बिना स्वयं को जीवित रखे

हुये हैं, वित्तीय रूप से लड़खड़ा रहे हैं। सरकार अनगिनत तरीकों, जिनमें कानून तथा वित्तीय रास्ते भी शामिल हैं, के जरिए इनका चलते रहना मुश्किल बना रही है। सरकार उन अंतिम चंद कार्डेजों को भी समाप्त कर रही है, जहाँ पब्लिक आलोचनात्मक कवरेज के लिये पहुँच सकती है।" ज्ञातव्य है कि "रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स" द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित वैश्विक प्रैस फ्रीडम इंडेक्स में वर्ष 2023 में भारत की 180 देशों में 161 वीं रैंक थी।गत वर्ष, यह दो रैंक ऊपर, अर्थात्, 161वें नम्बर पर रही, लेकिन अब भी पड़ोसी देशों, पाकिस्तान (152) तथा श्रीलंका (150) से काफी नीचे है।

विश्व आदिवासी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कहा कि इस समुदाय के लोगों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए उनकी समस्या पर सबका ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार को उनकी जल-जंगल-जमीन की लड़ाई को मांग स्वीकार कर, नौ अलग-अलग आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करना चाहिए।

उन्होंने गाँधी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि देश के मूल निवासी आदिवासी हैं और इस देश पर सबसे ज्यादा अधिकार उनका ही है, लेकिन भाजपा आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर कर उनकी जमीनों को छीनी रही है। आदिवासियों की ज़रूरत और कानून अलग है, इसलिए आदिवासी जिलों में पंचायती राज मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी ग्राम सभाओं को दिए कानून सर्वमान्य हैं, जिसका मतलब है कि गाँव में स्वशासन इन गाँवों के लोगों के माध्यम से होगा।

राजस्थान व तेलंगाना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) तक 125 गाँववात सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमने परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 54 हजार मेगावात से अधिक विद्युत क्षमता के लक्ष्य को वर्ष 2031-32 तक प्राप्त करने की दिशा में दूरगामी निर्णय लिए हैं।

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री मन्वु भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि राजस्थान की अपार सौर ऊर्जा एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर रही है। तेलंगाना की थर्मल ऊर्जा उत्पादन में दक्षता एवं राजस्थान की असीमित सौर क्षमता के लिए संपादित हुआ यह एमओयू ऊर्जा क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगा। ऊर्जा राज्य

मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा कि ऊर्जा विभाग तेलंगाना सरकार के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हुए इन परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने एक प्रस्तुतीकरण देते हुए एमओयू के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा (तेलंगाना) संदीप कुमार सुलतानिया, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलीक गुप्ता, आरजीयूपएल के सीएमडी देवेंद्र श्रुंगी, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के सीएमडी एन. बलराम सहित संबंधित विभागों के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

'केवल दिव्यांगता के आधार पर न्यायिक नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकते'

सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिबाधित व दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को बाहर रखने के नियम निरस्त किये

नयी दिल्ली, 03 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी (संबंधित पद के आवेदक) को न्यायिक सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति से बाहर रखने वाले मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम की शर्तों के उस भाग को निरस्त करते हुए कहा कि वे (दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित) भारत की न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के आवेदन के पात्र हैं। पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा, मध्य प्रदेश

■ सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों की पात्रता का आकलन करते समय उन्हे उचित सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट तरीका कि दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले अभ्यर्थी न्यायिक सेवा के पदों के लिए चयन में भाग लेने के हकदार होंगे। शीर्ष अदालत के समक्ष एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की मां ने पिछले साल मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा (पत्नी और मेधा शर्मा) नियम में शामिल उक्त नियम के खिलाफ पत्र याचिका दी थी, जिस पर अदालत ने स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया था। शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद तीन दिसंबर, 2024 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

अमेरिका ने सोच-समझ कर जाल फेंका था, जैलैंस्की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) इस घटना ने टुंग की उस छवि को भी धक्का पहुँचाया, जो एक ऐसे साहस सौदागर के रूप में बनी हुई थी, जो सबसे जटिल हालात में भी सौदे कर सकता है। जैलैंस्की-टुंग बैठक के फ्लॉप होने से अमेरिका को एक मल्टी-मिलियन डॉलर का सौदा गंवाना पड़ा, जिसमें दुर्लभ खनिज जैसे संसाधन शामिल थे, जिन्हें अमरीकी उद्योग लालच से देख रहे थे।

ओवल ऑफिस को झड़प ने डॉनल्ड ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से भी नुकसान पहुँचाया है। ट्रंप उसी दूर कर रहे थे कि एक बार जब वह दुश्मनी को ठंडा कर देंगे और रक्तपात खत्म कर देंगे, तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। अब ऐसा लगता है कि किसी भी शांति वार्ता में यूरोपीय शक्तियों को भी शामिल करना होगा।

जब यूरोपीय शक्तियाँ युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते की रूपरेखा तैयार करेगी तो आपस में बैठकर करेंगी और अमेरिका को बाद में सूचित करेंगी। हो सकता है कि अमेरिका रूस के साथ मिलकर ऐसे किसी कदम को रोکنने की कोशिश करे।

लंदन में यूरोपीय समिट में

सर्कुलर इकाँनमी इन्सैक्टिव के तहत स्टार्टअप को 2 करोड़ रूपए की सहायता मिलेगी

जयपुर, 3 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकाँनमी अत्यंत प्राथमिकी माध्यम है। इस व्यवस्था में अपशिष्ट को रिसाइकिल और रियूज किया जाता है जिससे ऊर्जा की खपत घटती है और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है।

शर्मा सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 12वें क्षेत्रीय श्री आर और सर्कुलर इकाँनमी फोरम समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि कचरा प्रबंधन और रिसाइकिलिंग को ज्यादा प्रभावी तरीके से किया जा सके। साथ ही, ट्यूटेड कांटर के उपयोग के लिए नई नीति तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता को 21 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर इसके दोगुने से भी ज्यादा यानी करीब 45 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। वेस्ट-टू-एनर्जी योजनाओं के तहत कंपोस्ट, आर्डीएफ, और जैविक उर्वरक उत्पादन पर भी जोर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्षेत्रीय "श्री आर" और सर्कुलर फोरम समारोह को संबोधित किया

■ केन्द्रीय आवास मंत्री खट्टर ने कहा कि सिटीज 2.0 के तहत 14 प्रदेशों के 18 शहरों में कचरा प्रबंधन संयंत्र तथा कचरे से खाद व ऊर्जा बनाने की परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू कराया जायेगा।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण क्षमता को 21 लाख टन से बढ़ाकर 45 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है।

दिया जा रहा है।

शर्मा ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन लगभग 400 प्रतिशत बढ़ कर 106 बिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर चुका है। चिंता की बात यह है कि इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक संसाधन बर्बाद हो जाते हैं और केवल 8.6 प्रतिशत ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापस आ पाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सर्कुलर इकाँनमी इंसेंटिव स्क्रीम लेकर आएगी, जो एमएसएमई और

स्टार्टअप को 2 करोड़ रुपये तक की सहायता देगी। इसके साथ ही राजस्थान व्हीकल स्कैपिंग पॉलिसी के माध्यम से पुराने वाहनों के निष्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि हम शून्य अपशिष्ट समाज का सपना साकार करने के लिए सर्कुलर इकाँनमी एलायंस नेटवर्क की स्थापना के जरिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे।

कार्यक्रम में केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सिटीज 2.0 एक ऐसी न्यूटी

पहल है जो इन्टीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाती है। इसके तहत 14 प्रदेशों के 18 शहरों में समयबद्ध रूप से परियोजनाओं को लागू कर कचरा प्रबंधन संयंत्र लगाने, कचरे से खाद, कचरे से ऊर्जा बनाने पर जोर दिया गया है।

कार्यक्रम में जापान, यूएन, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी वीडियो संदेश के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय शहरी विकास कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

इस अवसर पर नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्वा, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड, आंध्रप्रदेश और हरियाणा के शहरी विकास मंत्री, विभिन्न राज्यों के शहरी विकास विभागों के अधिकारीगण, नगरीय आयुक्त एवं महापौर उपस्थित रहे।

फिल्म "अनोरा" ने जीते 5 ऑस्कर अवॉर्ड

लॉस एंजलिस, 3 मार्च। 97वें अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) में फिल्म 'अनोरा' का जलवा रहा और उसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित पांच अवॉर्ड अपने नाम किये। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार फिल्म अनोरा के लिये शॉन बेकर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एडुइन ब्रोडी को फिल्म द बूटलिस्ट के लिये मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार माइकी मैडिसन को फिल्म अनोरा के लिये दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान कोरन कल्किन को फिल्म ए रियल पेन के लिये दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जोई सलदाना को एमिलिया पेरेज के लिये दिया गया।



विधायक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को सावचेत करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है कि वे बिना तथ्यों के गैरजिम्मेदाराना बात सदन में नहीं रखें। उन्होंने सदन से आग्रह किया कि इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ताकि इसकी पूरी जांच की जा सके। इस पर सदन ने प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया।बाद में कांग्रेस विधायकों ने इसका विरोध करते हुए सदन में नारेबाजी की और सदन से बहिर्गमन कर गए।

पेपर लीक मामले में फरार सुरेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पेपर पढ़ाया गया था, वहां भी प्रार्थी मौजूद नहीं था। वह करीब 11 माह से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने कहा कि प्रार्थी पर पेपर लीक के गिरोह में शामिल होकर काम करने का गंभीर आरोप है। वह फरार चल रहे सुरेश ढाका का भाई और मुख्य

अभियुक्त सुरेश विस्नोई का साला है। सुरेश के पकड़ में आने पर प्रार्थी की भूमिका के बारे में अन्य साक्ष्य भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट की एलडीसी पीठा और एसआई भर्ता में भी उसे गिरफ्तार किया गया है। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

ट्रंप और ज़ैलैंस्की के बीच फिर संवाद शुरू करना चाहता है फ्रांस

लंदन/पेरिस, 03 मार्च। फ्रांस और ब्रिटेन ने यूक्रेन में हवा, समुद्र और ऊर्जा अवसंरचना में एक मिनट के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है।

■ फ्रांस और ब्रिटेन ने हवा, समुद्र व ऊर्जा में एक माह के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है।

फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रॉन ने दैनिक समाचार पत्र ले फेकोर को यह जानकारी दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने रविवार को लंदन में यूक्रेन पर शिखर सम्मेलन से पहले घोषणा की कि पेरिस और लंदन युद्ध को रोक्ने के लिए एक योजना पर काम कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि शुरुआत में शत्रुता का अंत करने में जमीनी लड़ाई शामिल नहीं होगी क्योंकि युद्ध विराम के मामले में यह सुझावित करना बहुत मुश्किल होगा कि मोर्चे का सम्मान किया

गया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय सैनिकों की तैनाती में फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक भाग लेने के लिए तैयार हैं। मैक्रॉन ने ले फिगारो को बताया कि आने वाले हफ्तों में यूक्रेनी धरती पर कोई यूरोपीय सैनिक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि उपयोग युद्धविराम वार्ता के लिए करने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा, हम हार हाल में शांति चाहते हैं लेकिन किसी भी कीमत और बिना किसी गारंटी के।

हाई कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जैन की एकलपीठ ने ये आदेश जनता याचिका पर सुनवाई करते हुए।

सुनवाई के दौरान, सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि अदालत ने अप्रैल, 2024 में वूदी के सदर थाने में बजरी चोरी के इस मामले को जांच सीबीआई को सौंपी थी। वहीं बनावस और चंबल नदी के आसपास के समान मामलों में बजरी माफियाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। सीबीआई की ओर से कहा गया कि एक मामले में पूरूक आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। बनावस और चंबल के आसपास बजरी खनन से जुड़े ऐसे करीब 416 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वहीं, सीबीआई के पास संसाधनों की कमी और राज्य सरकार की ओर से उचित सहयोग नहीं मिलने के कारण इन प्रकरणों में सीबीआई जांच करने में समर्थ नहीं है। इसलिए इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई उच्चस्थ जांच एजेंसी है और वह ही संसाधनों की कमी की बात कह रही है। इसके साथ ही, अदालत ने सीबीआई निदेशक को 17 मार्च को व्यक्तिगतः या वीसी के जरिए पेश होकर इस पर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। गौरतलब है कि अदालत ने अप्रैल, 2024 में मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए मौखिक टिप्पणी की थी कि मामले में कार्रवाई नहीं होने से लगातार है कि पुलिस और खान विभाग की बजरी माफिया के साथ मिलीभगत है।

‘नार्थ इण्डिया...’ (प्रथम पृष्ठ का शेष) देना चाहिये। सभी भारतीय भाषाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं तथा सभी समानता के साथ पढ़ाई जानी चाहिए। फिल्माने में कुछ लोग राजनैतिक कारणों से इस्का विरोध कर रहे हैं। हमने एन.ई.पी. में यह कहीं नहीं कहा है कि केवल हिन्दी ही पढ़ाई जायेगी।’

सामना कर रहे हैं और रोजगार के लिए बाज़ार ढीला हो गया है। अब तक, रोजगार बढ़ रहा था, लेकिन अब इसके

'नरेगा लोकपाल की अपील सुनने..'

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के खिलाफ निकाली रिकवरी पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने ये आदेश सीमा शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाडा में पंचायती राज विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। गत जुलाई माह में नरेगा लोकपाल ने नरेगा में रोजगार प्रदान करने में असफल रहने पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ करीब साठ हजार रूपए की रिकवरी निकाल कर यह राशि नरेगा मजदूरों को देने के आदेश जारी कर दिए, जबकि याचिकाकर्ताओं ने सभी मजदूरों की ओर से काम मांगते ही जांच कार्ड जारी कर दिए थे। याचिका में कहा गया कि लोकपाल के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए नियम 13.4 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने अब तक अपीलीय प्राधिकरण का गठन नहीं किया है, जिसके चलते लोकपाल की ओर से जारी अवॉर्ड और वसूली गठन की अपील नहीं हो पा रही है।